



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क नियमाला)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2003

अंतिम निष्कर्ष

विषय: चाइनीज टाइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ(फ्रांस को छोड़कर) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच- अंतिम जांच परिणाम।

सं0 14/39/2002-डीजीएडी- वर्ष 1995 में^१ यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत;

क. प्रक्रिया

- जांच के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-
- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मसर्स अल्काली मैनुफैक्चरर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया (ए०एम०ए०आई०) (जिसे इसके पश्चात् याचिकाकर्ता कहा गया है) से एक लिखित याचिका प्राप्त हुई है

जिसमें चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) (जिन्हें इसके पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल से अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आमतौर पर कास्टिक सोडा (जिसके इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है। यह याचिका मैसर्स डी०सी०डब्ल्यू० लिमिटेड, मुंबई, मैसर्स गुजरात अल्कालीज एण्ड कैमिकल लिमिटेड, बडोदरा, गुजरात, मैसर्स सर्च कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिं० मुंबई, मैसर्स ग्रासिम इन्ड० लिमि० नगदा, मध्य प्रदेश, मैसर्स सिएल कैमिकल कम्पलैक्स, पटियाला, पंजाब, मैसर्स बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमि०, झारखण्ड, मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लिमि० उड़ीसा, मैसर्स आंध्रा शुगर लिमि०, तनाकू, डी०सी०एम० श्रीराम, नई दिल्ली, मैसर्स इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिं०, बडोदरा, मैसर्स स्टैंडर्ड अल्काली, मुंबई और मैसर्स डी०सी०एम० श्रीराम कन्सोलिडेटेड लिं०, नई दिल्ली द्वारा समर्थित थी।

(ii) प्राधिकारी ने दिनांक 8 अक्टूबर, 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु, जिन्हें कस्टम टेरिफ एक्ट 1975(आई०टी०सी० का 28151101, 28151102 और 28151200) की अनुसूची-1 के तहत वर्गीकृत किया गया।

(iii) याचिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनां के आधार पर सामान्यतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण के नियमों के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने व उसका विक्रय करने की लागत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का भी विश्लेषण किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम का पाटनरोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। निम्नलिखित कम्पनियों के उत्पादन के आंकड़ों की लागत के बारे में उचित तरीके से विचार किया गया व उनकी जांच की गई :-

1. मै० डीसीडब्ल्यू० लिं०, मुंबई
2. मै० गुजरात अल्कालीज एंड कैमिकल्स लिं०, बडोदरा
3. मै० सर्च कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिं०, मुंबई
4. मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिं०, नागदा (मध्य प्रदेश)
5. मै० एस०आई०ई०एल० कैमिकल्स कम्पलैक्स, पंजाब
6. मै० बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमि०, बिहार
7. मै० जयश्री कैमिकल्स लिं० उड़ीसा

8. मैं 0 आन्ध्रा शुगर लिंग, तनाकू
 9. मैं 0 इंडियन पैट्रो कैमिकल्स कारपो. लिंग दाहेज

(iv) प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गयी सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया ।

(v) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन ताइपेई, इण्डोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचों के बारे में दिनांक 8 जनवरी, 03 की अधिसूचना सं 0 14/39/2002-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए और हितबद्ध पक्षकारों को इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।

(vi) प्राधिकारी ने उन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच-परिणामों की एक प्रति प्रेषित की थी जिनको पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

(vii) प्राधिकारी ने नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को भी प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे प्रारंभिक जांच परिणामों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें ।

(viii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सुनने के लिए 22 अप्रैल, 2003 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, आयातकों एवं संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भाग लिया गया था। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से इस प्रकार प्राप्त लिखित अनुरोधों पर इन जांच-परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है ।

(ix) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को अपने द्वारा रखी गई सार्वजनिक

फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला रखा ।

- (x) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के लिए किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ।
- (xi) इस मामले में जांच की अवधि 1 जनवरी, 2002 से 30 सितम्बर, 2002 तक है ।
- (xii) *** इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना प्रदर्शित होती है जिसे नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा ऐसा ही माना गया है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद/समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचार

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोआक्साइड है जो सामान्यतया कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है । रासायनिक तौर पर कास्टिक सोडे को एन०ए०ओ०ए८० के रूप में जाना जाता है । यह एक अकार्बनिक रसायन है जिसे कस्टम टैरिफ एक्ट के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित कास्टिक सोडा के समान वस्तु है । यद्यपि सभी तीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग भारत में कास्टिक सोडा के विनिर्माण में कियाजा रहा है तथापि भारत में मरकरी सैल्स और मेम्ब्रेन सैल्स प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग कियाजा रहा है ।

मैसर्स नाल्को के विचार

3. मैसर्स नाल्को ने अनुरोध किया है कि कास्टिक सोडा द्रव्य और ठोस/टुकड़े अलग-अलग उत्पाद हैं और इन्हें वर्तमान जांच के लिए समान उत्पाद नहीं माना जा सकता है । यह निवेदन है कि विशेषकर एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में द्रव्य

कास्टिक सोडा के रूप का ही उपयोग विश्वभर में एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार ठोस/परतदार कास्टिक सोडा का उपयोग एल्यूमिनियम के उत्पादन में नहीं किया जा सकता है और यह वाणिज्यिक रूप से द्रव्य कास्टिक सोडा का प्रतिस्थापनीय नहीं है।

4. द्रव्य और ठोस कास्टिक सोडा के बीच अंतर द्रव्य में कम कास्टिक सोडा की सांद्रता और ठोस में अधिक सांद्रता के कारण है। अतः यह निवेदन है कि ठोस/परतदार और द्रव्य कास्टिक सोडा को एक समान उत्पाद नहीं माना जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटन हो रहा है और क्या घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो रही है, केवल ठोस कास्टिक सोडा पर विचार किया जाना चाहिए। कास्टिक सोडा द्रव्य कास्टिक सोडा ठोस/परतदार में आगे और विनिर्माण प्रक्रिया शामिल होती है जिससे उत्पादन की लागत में भिन्नता आती है। बाजार मूल्य, प्रहस्तन, भण्डारण एवं परिवहन इत्यादि से उनके अंतिम प्रयोग में भिन्नता आती है।

5. मैं नाल्को निवेदन करता है कि जांचके लिए एकमात्र प्रवर्तन नाल्को की निविदा का कथित घटाहोना है, इसलिए विचाराशीन उत्पाद निविदा द्वारा प्राप्त उत्पाद होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि निविदा द्वारा प्राप्त उत्पाद द्रव्य कास्टिक सोडा का जिसका एकमात्र उपयोग नाल्को और विश्वभर में एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा किया जाता है। यह निवेदन है कि वर्तमान जांच में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कास्टिकसोडा के अन्य रूपों पर विचार करने से पाटन के मूल्यांकन पर विकृतकारी प्रभाव पड़ता है। नाल्को का सादर निवेदन है कि विश्व भर में अल्यूमिनियम उद्योग की प्रथा के अनुसार केवल एल्यूमिनियम विनिर्माता द्रव्य कास्टिक सोडा की खरीद करते हैं और ठोस कास्टिक सोडा की खरीद नहीं करते क्योंकि इसकी खरीद करने से मुख्य निर्माण कार्यकलापों से संसाधनों को सहायक क्रियाकलापों में अर्थात् ठोस कास्टिक सोडा का द्रव कास्टिक सोडा में परिवर्तन लगाने के अलावा विनिर्माताओं को अधिक लागत लगानी पड़ती है। नाल्को इस बात की प्रशंसा करता है कि माननीय प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में यथानिर्दिष्ट उपर्युक्त मुद्दे के उसके दावों को स्वीकार कर लिया है।

6. यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने जांच की मांग करने के बजाय ठोस एवं परतदार कास्टिक सोडा जिसका निर्माण करना महंगा पड़ता है, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इनके बारे में और प्रसंस्करण करने की जरूरत पड़ती है, पर लगाई गई उत्पादन लागत की जांच समेत उनकी उत्पादन लागत में सहायता करने

की मांग की है। इसके अलावा अत्यधिक कास्टिक सोडा सांद्रता के कारण ठोस एवं परतदार कास्टिक सोडा में वाणिज्यिक अवधारणा अथवा बाजार मूल्य में भिन्नता आती है जिसका प्रदर्शन बाजार में उनकी उच्च कीमतों में होता है।

7. यह भी निवेदन है कि निविदा के अंतर्गत केवल 30,000 डीएमटी का आयात किया गया है जो देश की कुल मांग का एक सूक्ष्म भाग बनता है जो याचिकाकर्ता के अपने स्वीकारोक्ति के अनुसार लगभग 15,55,200 एमटी है। आयातित मात्रा देश में कास्टिक सोडा के कुल मांग का केवल एक प्रतिशत बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता के कथित घाटे के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता।

प्राधिकरी द्वारा जांच

8. चाहनीज ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के मूल का अथवा वहां से निर्यातित मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोआक्साइड(रासायनिक नाम एन.ए.ओ.एच.)जिसे साधारणतया कास्टिक सोड के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक झाग वाला बहुत ही क्षारय और गंधहीन रसायन है और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पत्त्य और पेपर, न्यूजप्रिंट, बिस्कोज यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमिनियम काटन, टेक्सटाइल्स, टाइलट और लांड्री सोपस, डिटरजेंट, डाई स्टफ, ड्रग्स और औषधि बनाने, पेट्रोलियम शुद्धिकरण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का दो प्रकारों में अर्थात् तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं द्वारा अर्थात् मरक्यूरी शैल प्रोसेस, डाइफ्रैम प्रोसेस और मेम्ब्रेन प्रोसेस द्वारा सज्जीदार पानी (ली) और ठोस (सोलिड) रूप में उत्पादित किया जाता है। विभिन्न विशेषताओं के अनुसार, इन प्रक्रियाओं में भिन्नता का तात्पर्य उत्पाद में भिन्नता से नहीं है। कास्टिक सोडा, कस्टम शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत है। आई.टी.सी. के 8 डिजिट के वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद को कस्टम शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, मौजूदा वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. यह एक सुविदित तथ्य है कि भारत समेत विश्व भर में कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है और इसकी बिक्री मुख्य रूप से द्रव्य रूप में जैसे कि (1) कास्टिक सोडा का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है अतः कम सांद्रता के कारण

अत्यधिक परिवहन लागत का भुगतान करने के पश्चात् भी द्रव्य रूप में परिवहन जिसके परिणामस्वरूप क्रता को कम प्रभावी लागत देनी पड़ती है, (2) परतदार कास्टिक सोडा को बदलने के लिए अतिरिक्त लागत की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कास्टिक सोडा ठोस रूप का प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां द्रव्य रूप की जरूरत पड़ती है । कास्टिक सोडा का उत्पादन एवं बिक्री मुख्य रूप से द्रव्य रूप में किया जाता है क्योंकि कास्टिक सोडा का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है इसलिए द्रव्य रूप में इसके परिवहन से कम सांद्रता वाले लिविंड कास्टिक सोडा के लिए अधिक परिवहन का भुगतान करने के पश्चात् भी कम प्रभावी लागत आती है अतः प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि कीमतों में भिन्नता सांद्रता में भिन्नता ठोस रूप बनाने के लिए अपेक्षित बढ़ती हुई परिवहन लागत की तुलना में द्रव्य रूप में परिवहन की लागत अधिक होने के कारण है ।

10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित माल संबद्ध देशों में उत्पादित और निर्यातित माल के समान है यह दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता स्वदेश में उत्पादित और आयातित माल का अदल बदल करके प्रयोग कर रहे हैं अतः प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि इस जांच में कास्टिक सोडा के सभी रूप, द्रव्य और ठोस दोनों रूप शामिल हैं और संबद्ध माल के सभी भिन्न-भिन्न रूपों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जरूरत के आधार पर कर रहे हैं । प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और संबद्ध देशों से निर्यातित माल की प्रतिस्थापनीयता और अंतःपरिवर्तनीयता और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल को ध्यान में रखते हुए निर्यातित संबद्ध माल और स्वदेश में उत्पादित संबद्ध माल को उपर्युक्त नियम 2 भाग 2 के अनुसार समान वस्तुएं मानते हैं । प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ केवल डीएमटी आधार पर उचित तुलना की है ।

ग. इण्डोनेशिया सरकार के विचार

11. यद्यपि यह दावा किया जाता है कि घरेलू उद्योग निविष्टि के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, तथापि इण्डोनेशिया सरकार यह बात नोट करती है कि अन्य भारतीय विनिर्माताओं का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से से कहीं अधिक है ।

12. करार के अनुच्छेद 5.4 के अंतर्गत अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए इण्डोनेशिया सरकार प्राधिकारी से उन क्रियाविधियों को स्पष्ट करने का अनुरोध करती है जो यह निर्धारित करने के लिए अपनायी गयी थी कि आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया था ।

13. इस निर्धारण से परिकलन का कोई ब्यौरा नहीं मिलता है जिसके फलस्वरूप 299.87% पाटन मार्जिन हुआ है । चूंकि प्रयुक्त सूचना पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, इसलिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5.1 के अंतर्गत गोपनीयता बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । इण्डोनेशिया सरकार यह अनुरोध करती है कि सही परिकलन के ब्यौरों का खुलासा किया जाए ।

14. इसके अतिरिक्त जहां जांच अधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग करता है वहां सावधानी बरतने की जिम्मेदारी होती है । इस संबंध में, लगभग 300% के कथित पाटन मार्जिन का प्रभाव प्रयुक्त साक्ष्यों की गुणवत्ता एवं यथार्थता पर पड़ता है । इस प्रकार, हमारी सरकार जांच अवधि को शामिल करने के लिए अंतिम निर्धारण हेतु सामान्य मूल्य के बारे में इण्डोनेशिया में प्रकाशित सूचना प्राप्त करना चाहती है ।

15. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.7 में वास्तविक क्षति एवं उसके खतरे का निवारण किया गया है । इस बारे में हम प्राधिकारी से जांच अवधि के भीतर उन परिवर्तित परिस्थितियों का ब्यौरा देने का अनुरोध करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें कथित पाटन से क्षति होगी ।

16. भारत में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन काफी प्रभावशाली है । घरेलू क्षमता उपयोग में विस्तार होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान अभी भी वृद्धि हुई है । इसी अवधि के दौरान स्टॉक में गिरावट आयी और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि जारी रही ।

17. यद्यपि जांच अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप में कथित पाटित आयातों में वृद्धि हुई है तथापि वे अभी भी घरेलू मांग के 13% से भी कम का प्रतिनिधित्व करते हैं । इण्डोनेशिया की सरकार यह समझती है कि आयातों की मात्रा से घरेलू उद्योग को कथित क्षति नहीं हुई है ।

18. संबद्ध भाल के विनिर्माण की भिन्न-भिन्न उत्पादन प्रक्रिया का लागत और बिक्री कीमतों पर गमीर प्रभाव पड़ सकता है और घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति चयनित उत्पादन प्रक्रिया के कारण हो सकती है।

19. यह नोट किया गया है कि इस कार्रवाई में कम शुल्क सिद्धान्त लागू नहीं किया गया है। इंडोनेशिया की सरकार इसबात की सराहना करेगी कि यदि यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि एलडीपी का परिकलन क्यों नहीं किया गया है।

20. हम उभीद करेंगे कि जांचकर्ता प्राधिकारी प्रारंभिक उपाय करने के पश्चात् कीमत उतास-चढ़ाव का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे और यदि यह पाया जाता है कि आयात पतिवंधित हैं तो अन्तिम निर्धारण के लिए ग्राहक पर प्रभाव की दुबारा जांच की जाएगी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै0 अल्काली ऐन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), दिल्ली द्वारा दायर की गई है। एसोसिएशन में भारत में कास्टिक सोडा के सभीघरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व है। यह याचिका स्पष्ट रूप से निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है अर्थात् मै0 डी.सी. डब्ल्यू लिमिटेड, मुंबई, मै0 गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा, मै0 सर्च कैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई, मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागदा (म.प्र.), मै0 सीआईईएल कैमिकल्स काम्पलैक्स, पंजाब, मै0 बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमिटेड, झारखण्ड, मै0 जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड, उड़ीसा और मै0 आन्ध्रा शुगर लिमिटेड, तनाकू। ये याचिकाकर्ता कंपनियां उत्पादन की जा रही सम्बद्ध वस्तु के 40.09% का प्रतिनिधित्व करती हैं और मै0 इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा, मै0 स्टैर्डर्ड अल्काली, मुंबई और मै0 डी.सी. डब्ल्यू श्रीराम कंसोलीडेटिड लिमिटेड, नई दिल्ली के समर्थन से ये घरेलू उद्योग के उत्पादन के 55.67% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच डब्ल्यू टी ओ करार के दिशानिर्देशों के अनुरूप पाटनरोधी नियम के अनुसार की जा रही हैं। समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के समर्थन अथवा विरोध की सीमा की जांच के आधार पर यह जांच शुरू की जाती है कि आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है। आवेदन-पत्र को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से

प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा। इस आवेदन-पत्र का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाता है जिनका संयोग उत्पादन आवेदन-पत्र का समर्थन अथवा विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस समूह द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन का 50% से अधिक बनता है। तथापि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन के 25% से कम उत्पादन वाले आवेदन के समर्थनकर्ता घरेलू उत्पादक होने पर कोई जांच शुरू नहीं की जाती।

23. अनुच्छेद 5.4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि आवेदन को इस स्थिति में 'घरेलू उद्योग द्वारा समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उक्त भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता हो। इस मामले में अल्कली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता है और कास्टिक सोडा के अधिकारी भारतीय उत्पादक उक्त एसोसिएशन के सदस्य हैं। इसके अलावा, कास्टिक सोडा के किसी भारतीय उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है। अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार याचिका के स्तर का निर्धारण करने के बाद प्राधिकारी ने जांच शुरू की थी।

24. जहां तक मांग में बाजार हिस्से का संबंध है यह नोट किया जाता है कि मै0 इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि�0, बडोदरा, मै0 स्टैंलर अल्कली, मुम्बई और मै0 डी.सी.एम. श्रीराम कन्सोलीडेटिड लि�0, नई दिल्ली के लागत निर्धारण संबंधी पूर्ण सूचना के साथ याचिका का समर्थन किया है तथा समर्थकों के साथ इन कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता है।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ में कास्टिक सोडा की घरेलू कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अल्कली से प्राप्त कीमत के आधार पर किया गया है क्योंकि इंडोनेशिया के किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और अपने घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत प्रस्तुत नहीं की है। निर्यात कीमत का निर्धारण वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया गया है। जहां तक निर्यात कीमत की गणना का संबंध है प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित सूचना पर विश्वास किया। डीजीसीआईएंडएस की सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार में एक समय में एक ही प्रकार की क्षति की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वस्तुतः यदि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होती है तो पाटनरोधी शुल्क को तब तक लगाना वांछनीय नहीं हो सकता है जब तक कि इसबात को दर्शाने का पर्याप्त साक्ष्य न हो कि इस प्रकार की क्षति पाटित आयातों के कारण जारी रह सकती है जिसके लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पाटनरोधी उपायों द्वारा निवारण अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति के खतरे के संबंध में दर्ज जांच परिणामों को इस आश्य के मुख्य जांच परिणामों की घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, के अनुपूरक परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए।

27. जहां तक अनुच्छेद 3.4 के अंतर्गत क्षति के कुछेक कारकों की जांच का संबंध है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के विभिन्न मापदण्डों की जांच की थी। जहां तक कुछ मापदण्डों में सुधार का संबंध है यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कुछेक मापदण्डों में सुधार का तात्पर्य यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के लिए एक ही मापदण्ड पर्याप्त हो सकता है। आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इतनी कम अवधि में उसका मांग में हिस्सा काफी अधिक 13% हो गया है। उक्त वृद्धि को नगण्य नहीं माना जा सकता।

28. इस मामले में कीमत कटौती भी अत्यधिक हुई है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ताओं के लागत संबंधी आंकड़ों का सत्यापन किया और उद्योग की उचित बिक्री कीमत की जांच की तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाटित आयातों की पहुंच कीमत इतनी कम है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती होती है।

29. जहां तक कम शुल्क संबंधी नियम के बारे में इंडोनेशिया सरकार की चिंता का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीएडी की प्रथा यह है कि पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जाए जिसे यदि वसूल किया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी।

30. प्राधिकारी इंडोनेशिया सरकार की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कीमत ह्लास/न्यूनीकरण जैसे कारकों को लागत संबंधी वास्तविक आंकड़ों के अनुसार लिया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत पर विचार किया है जो पाटित

आयातों के कारण कीमत हास/न्यूनीकरण के प्रभाव के विश्लेषण हेतु उत्पादन की वास्तविक लागत से अधिक संतुलित है।

31. अन्य देशों से हुए आयात या तो न्यूनतम हैं या निर्यात कीमत अधिक है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच और इसउत्पाद विशिष्ट जांच में अन्य उत्पादों की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। अन्य उत्पादों के कारण भागीदार कंपनियों को हुई क्षति के बारे में यह नोट किया जा सकता है कि समस्त याचिकाकर्ता कंपनियों ने केवल संबद्ध वस्तु के बारे में ही सूचना प्रस्तुत की है।

33. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस बात की चिंता का कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य भारतीय उत्पादकों के कारण हो सकती है। इसके विपरीत इस आशय का सकारात्मक साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण बाजार गंवाया है, कीमतों में गिरावट आयात कीमतों में भारी गिरावट के कारण आई तथा घरेलू उद्योग का प्रतिकूल निष्पादन पाटित आयातों के कारण रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा विश्व भर में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी मैम्ब्रेन प्रोसेस का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए प्रौद्योगिकी में अन्तर से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। चूंकि भारतीय पाटनरोधी नियमों में कम शुल्क के नियम का प्रावधान है, इसलिए उत्पादन की उच्च लागत के कारण इस प्रकार का कोई प्रभाव स्वतः ही सीमित हो जाता है।

घ. यूरोपीय संघ के विचार

34. इस बात का युक्तिसंगत तर्क नहीं दिया जा सकता कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जिस सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना की है वह गोपनीय स्वरूप की है। यूरोपीय निर्यातकों के संबंध में और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सामान्य मूल्य के आंकड़े 'प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अल्कली' से लिए गए थे। निर्यात कीमत को 'डीजीसीआईएंडएस से उनके (याचिकाकर्ताओं)द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर' निर्धारित किया गया बताया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि वह विस्तृत सूचना उपलब्ध की जाए

अथवा कराई जाए जिसके अनुसार इन प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि की गई थी।

35. यद्यपि अनन्तिम शुल्क पहुंच मूल्य और लक्षित कीमत के बीच के अन्तर पर आधारित अलग-अलग होती है। यह लक्षित कीमत अलग-अलग क्यों होती है। इसके अलावा उसी पैराग्राफ में यह उल्लेख है कि पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन के बराबर होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है जब यह ऐसे लक्ष्य पर आधारित है जो पाई गई क्षति के स्तर पर आधारित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ में कास्टिक सोडा की घरेलू कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अलकली से प्राप्त कीमत के आधार पर किया गया है क्योंकि ईयू (फ्रांस को छोड़कर) के किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और अपने घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत प्रस्तुत नहीं की है। निर्यात कीमत का निर्धारण वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

37. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीएडी की प्रथा यह है कि पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जाए जिसे फिर वसूल किया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। ऐसा इस कारण से किया जाता है कि संदर्भ कीमत (लक्षित कीमत) उद्गम देश के अनुसार अलग-अलग होती है।

ड. घरेलू उद्योग

38. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु का विनिर्माण और उससे जुड़ा कोई कार्यकलाप करते हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है किन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते

हैं अथवा वे स्वयं उस वस्तु के आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।'

39. घरेलू उद्योग की ऊपर दी गई परिमाण नियमावली के नियम 5 के द्वारा आगे और स्पष्ट की गई है, जो इस प्रकार है:-

'.....आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि उसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उक्त भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता हो।

40. यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से अल्काली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), दिल्ली द्वारा दायर की गई है। एसोसिएशन में भारत कास्टिक सोडा के सभी घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व है। यह याचिका स्पष्ट रूप से निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है अर्थात् मैसर्स डी०सी०डब्ल्यू० लिमिटेड, मुंबई, मैसर्स गुजरात अल्कालीज एण्ड कैमिकल लिमिटेड, बडोदरा, मैसर्स सर्च कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिं० मुंबई, मैसर्स ग्रासिम इन्ड० लिमि० नागदा (मध्य प्रदेश), मैसर्स सीआईईएल कैमिकल कम्प्लैक्स, पटियाला, पंजाब, मैसर्स बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लिमि०, झारखण्ड, मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लिमि० उड़ीसा, और मैसर्स आंध्रा शुगर लिमि०, तनाकू। ये याचिकाकर्ता कंपनियां उत्पादन की जारही सम्बद्ध वस्तु के 40.09% का प्रतिनिधित्व करती हैं और मै० मैसर्स इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिं०, बडोदरा, मैसर्स स्टैंडर्ड अल्काली, मुंबई और मैसर्स डी०सी०एम० श्रीराम कन्सोलिडेटेड लिं०, नई दिल्ली के समर्थन से 55.67% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

41. 'पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार, समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु का विनिर्माण और उससे जुड़ा कोई कार्यकलाप करते हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है किन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उस वस्तु के आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।' इसके अतिरिक्त पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार

निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के अंतर्गत दिए गये आवेदन पर कोई जांच शुरू नहीं करेंगे जब तक यह समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए आवेदन के समर्थन या विरोध के स्तर की जांच के आधार पर निर्धारित नहीं होता कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा रहा है बशर्ते कि कोई भी जांच शुरू नहीं की जायेगी यदि घरेलू उत्पादक स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से कम के लिए आवेदित मात्रा का समर्थन करते हैं।

42. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक जिन्होंने याचिका का समर्थन किया है, कुल घरेलू उत्पादन का 50% बनाते हैं और किसी भी घरेलू उत्पादक द्वारा याचिका का कोई विरोध नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) (क) और (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करते हैं एवं नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन :

मै0 नाल्को के विवार

43. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका श्रामक है और वास्तविक तथ्यों को छिपाती है। यदि बिना स्वीकार किए यह माना जाता है कि याचिका में सही एवं समुचित विवरण हैं, तब यह सादर निवेदन किया जाता है कि याचिका में जांच शुरूआत के सही ठहराने तक के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। पूर्वोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में याचिका अनुरक्षणीय नहीं है यह तर्क मानना समग्रतः स्तुत्य नहीं है।

44. नाल्को की निविदा के संबंध में, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति म आपूर्तिकर्ता को किसी भी देश से आपूर्ति करने का विकल्प देते हुए यह निवेदन किया गया है कि नाल्को द्वारा वहन किए जाने वाले कर भार की कटौती करने के लिए भी इसको समाविष्ट किया गया है, जिसमें नाल्को को समान शुल्क का भुगतान करना होगा। इसे अत्यधिक सावधानी वाले विषय के रूप में रखा गया ह, क्योंकि सभी देशों में यह उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर उपलब्ध होने के कारण, इसकी आपूर्ति किसी भी स्रोत से की जा सकती है। नाल्को ने निविदा में इस तरह के प्रावधान किए हैं, जिससे पाटनरोधी शुल्क के कारण इस पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व का भार न पड़े। यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति में नाल्को के हितों

की रक्षा हेतु निविदा को निलंबित करने का प्रावधान भी रखा गया है। यदि वैश्विक प्रेस निविदा में अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर प्राप्त तथ निविदा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व जैसे प्रावधानों का रखा जाना आदि जैसी बातें कंपनी में नहीं होती हैं तो नाल्को द्वारा लेखा परीक्षा, सतर्कता आदि जैसे भारत सरकार के विभिन्न अभिकरणों को उत्तर दिया जाना अपेक्षित होगा। नाल्को नहीं बल्कि याचिकाकर्ता, इस निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए दोषी हैं, चूंकि उसने वर्तमान जांच में अंतर्राष्ट्रीय कास्टिक सोडा के उत्पादन के सभी स्रोतों को शामिल किया है।

45. याचिका में वर्ष 2000-2001 में 33,540 मी.टन के कुल आयात होने का उल्लेख किया गया है और जांच की अवधि में इसका उल्लेख 1,97,013 मी.टन के रूप में किया गया है। सविनय अनुरोध किया जाता है कि इसके लिए जांच की आवश्यकता है क्योंकि चीन और कोरिया से आयात हेतु उसी कास्टिक सोडा की पूर्व पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया था कि वर्ष 2001-2002 के दौरान 93,261 मी.टन के कुल आयात हुए थे। यह इंगित किया जा सकता है कि कोई भी याचिकाकर्ता कास्टिक सोडा के आयात करने के लिए नाल्को की निविदा संबंधी मांग को पूरा नहीं कर सका है। अतः घरेलू उद्योग या तो भाग न लेते हुए अथवा पूर्ण सहयोग देते हुए उक्त आयात किए और यह तर्क नहीं दिया जा सका कि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाई है।

46. चूंकि इस पाटनरोधी शुल्क का आधार सिर्फ नाल्को द्वारा किया जाने वाला आयात है तथा नाल्को केवल तरल कास्टिक सोडा का आयात करता है। इसलिए पाटन के निर्धारण करने तथा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या स्वदेशी उद्योगों को क्षति हो रही है, केवल तरल कास्टिक सोडा पर विचार किया जाना चाहिए। जैसाकि पहले सूचित किया गया था, कास्टिक सोडा द्रव्य, कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स से सर्वथा भिन्न है क्योंकि ठोस फ्लेक्स की विनिर्माण प्रक्रिया और अधिक लंबी होती है, जिससे उत्पादन लागत में काफी अंतर आ जाता है। चूंकि कास्टिक सोडा ठोस तथा फ्लेक्स के लिए हैंडलिंग, भंडारण तथा परिवहन, कास्टिक सोडा द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, इसलिए उनके उपयोग के तरीके एवं बाजार मूल्य भी भिन्न हैं।

47. याचिकाकर्ता ने अपने अगोपनीय रूपांतर में विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा पेशकश की गई कीमतों को दर्शाया है, किंतु वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के अंतर्गत आने

वाली घरेलू पार्टियों द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई कीमतों को जानबूझकर नहीं दर्शाया है। चूंकि ये कीमतें, विदेशी कीमतों के काफी करीब हैं, इसलिए स्वदेशी उद्योगों को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है।

48. क्लोर अल्कली उद्योग की सही लाभप्रदता का निर्धारण करने के लिए क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा दोनों की राजस्व वसूली को अभिज्ञात करना आवश्यक है, जोकि सामान्य नमक के इलेक्ट्रानिक विखंडन से उत्पन्न होने वाले सह-उत्पादक हैं। कास्टिक सोडा का उत्पादन करने वाली अभिक्रिया में कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन का उत्पादन 1:0:9 के अनुपात में होता है। यह एक वाणिज्यिक तथ्य है कि क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा दोनों की प्राप्ति एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है तथा विनिर्माता प्रत्येक की कीमत का निर्धारण इलेक्ट्रो केमिकल यूनिट (ईसीयू) अर्थात् दोनों से होने वाली कुल वसूली के न कि केवल एक पदार्थ की वसूली, के आधार पर करते हैं।

49. कास्टिक सोडा और क्लोरीन की कीमतों में लगभग एक दूसरे की कीमत परिलक्षित होती है और इन उत्पादों की कीमतें एक दूसरे के अनुपात में होती है। अतः जब क्लोरीन की कीमत उच्च होती हैं तो कास्टिक सोडा की कीमत कम होती है और विलोमतः भी यही स्थिति होती है।

घरेलू उद्योग के विचार

50. भारतीय कास्टिक सोडा उद्योग बड़े पैमाने पर भारत में कास्टिक सोडा की सारी मांग को पूरा करने में सफल रही है। भारतीय उद्योग वर्ष 1975 से अपनी मांग में आत्मनिर्भर रहा है। कास्टिक सोडा आयातों की उस सूची में रहा है जिस ओजीएल के तहत अनुमत किया गया है, विशेषकर 1980-81 से वास्तविक उपयगकर्ताओं के लिये। तथापि, भारतीय उद्योग की मूल्य निर्धारण की नीति के कारण आयात सीमित रहे। चाइनीज ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) में उत्पादकों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता उनके खुद के देश में मांग की अपेक्षा काफी अधिक है। इसके अलावा, कई अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ संबद्ध देशों में उत्पादक भारत को निर्यात करना आकर्षक समझ रहे हैं। इन देशों में अत्याधिक क्षमता से उत्पादकों पर बहुत ही दबाव पड़ रहा है कि वह अपने देश से बाहर बाजार खोजें। परिणामस्वरूप, चाइनीज ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के निर्यातकों ने भारत को निर्यात किये जाने के लिये बहुत ही कम मूल्य उद्धृत किये हैं। इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि इन देशों

के उत्पादकों ने कई बार भारत को सीधे ही अपनाई सप्लाई के लिये प्रस्ताव नहीं किया है। इन देशों के मूल से कास्टिक सोडा की सप्लाई के लिये तीसरे देशों में व्यापारियों द्वारा काफी मात्रा प्रस्तावित की गई है। इन व्यापारियों द्वारा किये जा रहे प्रस्ताव में जाहिव राना तौर पर इन व्यापारियों ने अपना मार्जिन भी शामिल किया होगा। अतः उन देशों में उत्पादकों द्वारा उद्धृत किये गये मूल्य अभी भी कम बने हुए हैं। याचिकाकर्ताओं का विश्वास है कि प्रस्तावित किये जा रहे ये मूल्य, उत्पादन के सहबद्ध किये गये मूल्य से काफी नीचे हैं। इस प्रकार चाइनीज ताइ, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फांस को छोड़कर) के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में कास्टिक सोडे के पाटन के तरीके को अपनाया है।

51. अधिकांश भारतीय उत्पादकों के पास बहु उत्पाद संयंत्र हैं और वे 100% क्लोरीन के प्रयोग केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए करते हैं तथा कास्टिक सोडा एक उपोत्पादन है। वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग और उलट है।

52. नाल्को द्वारा दिया गया विवरण गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा विचारित कीमतें लाइ के लिए हैं और जिनमें फ्लेक्स शामिल नहीं हैं, जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में दी गई सूचना से स्पष्ट है।

53. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में कास्टिक सोडा के ज्ञात निर्यातकों और उत्पादकों को जांच आरंभ संबंधी सूचना के साथ प्रश्नावली इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे अपने कास्टिक सोडा के उत्पादकों तथा निर्यातकों को जांच शुरूआत संबंधी सूचना तथा प्रश्नावली का उत्तर देने को कहें। तथापि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार की स्थिति में, निर्दिष्ट प्राधिकारी का जांच प्रक्रिया में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का प्रयोग करना न्याय संगत है। सामान्य मूल्य एक प्रमुख पत्रिका क्लोर अल्कली में प्रकाशित कीमतों पर आधारित है। तथापि, इंडोनेशिया के मामले में यह अनुरोध किया गया है कि जांच अवधि में आयात कीमतें इतनी कम थीं कि इनसे संबद्ध देशों के उत्पादकों को अपनी उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं हो पा रही थीं। इसलिए क्लोर अल्कली की कीमतें व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हो सकती हैं। वस्तुतः याचिकाकर्ताओं को इस बात की पूरी आशंका है कि यह निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त न होने का कारण रहा है। इन देशों के उत्पादकों को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्लोर अल्कली में उद्धृत कीमतें बहुत कम हैं और ये व्यापार के सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण में सफल नहीं हो पाएंगी।

54. कास्टिक सोडा के मामले में घरेलू उद्योग को एक के बाद एक स्रोतों से पाटन के कारण क्षति उठानी पड़ रही है। वर्तमान जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस उत्पाद के संबंध में चौथी जांच है। घरेलू उद्योग के पास नये-नये देशों से एक के बाद एक स्रोत से पाटन होने के कारण पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्त्ताओं द्वारा पहले से उल्लिखित और यहां नीचे पुनः उद्धरित नालकों की निविदा दस्तावेज शर्ते इस संबंध में आंखें खोल देने वाली हैं:

‘आर्डर दिये जाने के बाद भारत सरकार द्वारा पाटन रोधी शुल्क लगाने की दशा में आपूर्तिकर्ता उसी मूल्य पर भी आर्डर की शर्तों पर अन्य गैर पाटन रोधी स्रोत से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्न करेगा। भारत सरकार द्वारा पाटन रोधी शुल्क लगाने की तिथि से गैर-पाटन रोधी स्रोतों से सामग्री का प्रबन्ध करने के लिए क्रेता द्वारा अनुमति समय, तीस दिन होगा। तथापि, यदि विक्रेता उपर्युक्त के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहता है तो क्रेता को यह अधिकार है कि वह किसी भी पक्ष पर वित्तीय देयता के बगैर संविदा की शेष मात्रा के लिए आर्डर को समाप्त कर दे। इसमें वह शिपमेंट शामिल नहीं होगा जो कि पारगमन में है।’

प्राधिकारी द्वारा जांच

55. धारा 9 के (1)(ग) के अंतर्गत, किसी मद के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

- (i) समान वस्तु के लिए सामान्य व्यापार के रूप में तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपयोग के निमित्त हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो, या
- (ii) जब सामान्य व्यापार के रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती हो, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगस्थ
- (क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात, निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उपर्युक्त अन्य देश से किया जाए जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएः या
- (ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपर्युक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाए।

56. बशर्ते कि मूल के देश से अन्य के उस देश से जहां यह वस्तु निर्यात के देश के माध्यम से केवल जहाज से भेजी गई हो अथवा इस प्रकार की वस्तु का निर्यात किये जाने वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता अथवा निर्यात किये जाने वाले देश में इसका काई तुलनात्मक मूल्य न हो, वस्तु का आयात किये जाने की दशा में सामान्य मूल्य, उद्गम के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा ।

57. प्राधिकारी ने उपर्युक्त धारा के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यातकों को इस जांच से संगत सूचना प्रस्तुत करने और टिप्पणियां, यदि कोई हों, करने का अवसर प्रदान किया है । प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को भी लिखा था । प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) (ग) के अनुसार निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं, केवल मै0 सोलवे बेल्जियम ने इसका उत्तर दिया जो अपूर्ण था । किसी भी निर्यातक ने प्रारंभिक जांच परिणामों का उच्चर नहीं दिया था और पाटन या क्षति किसी के संबंध में टिप्पणी नहीं की थी ।

58. क्लोरीन के बारे में मै0 नालको द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कास्टिक सोडा की प्रत्येक इकाई के लिए एक विशेष मात्रा में क्लोरीन का भी उत्पादन होता है । तथापि यह भी सत्य है कि क्लोरीन खतरनाक होती है, इसलिए इसका मुक्त रूप से परिवहन नहीं किया जा सकता है । भारत में कास्टिक सोडा संयंत्रों को 'कास्टिक सोडा संयंत्रों के रूप में स्थापित किया गया है न कि क्लोरीन संयंत्रों के रूप में; इसलिए उद्योग को उस प्रयोजन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है । जब भारत में उत्पादक क्लोरीन को प्रचालित कीमतों पर बेचते हैं, तो इसके लिए इस जांच में संगत स्थानों पर आकलन किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मात्रा में कास्टिक सोडा की प्रत्येक इकाई के साथ एक विशेष मात्रा में क्लोरीन उत्पादित होती है । इस प्रकार, यह भली-भांति ज्ञात है कि एक विशेष क्षमता वाले कास्टिक सोडा संयंत्र से कितनी मात्रा में क्लोरीन का उत्पादन होगा । यह उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा गया एक उत्पाद है और प्राधिकारी ने इस जांच में इनके लागत आंकड़ों की जांच एवं सत्यापन किया था ।

यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर)

क. सामान्य मूल्य

59. प्राधिकारी ने खंड 9 का (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिये सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी । मै0 बी0ए0एस0एफ0, बैल्जियम, मै0 बी0ए0एस0एफ0, जर्मनी, मैसर्स बेयर शैल आइसोथानेट्स, एन0 वी0 बैल्जियम ने उल्लेख किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है । मैसर्स सोलवे, बैल्जियम ने उन्हें बताई गई कमियों को दूर नहीं किया था और जांच के लिए अपेक्षित निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में सूचना प्रस्तुत नहीं की थी । निर्यातक ने पाटन और क्षति पर अपनी टिप्पणियाँ नहीं दी थी ।

60. अतः यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अपर्याप्त एवं अपूर्ण उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त जानकारी पर विश्वास किया है । इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अल्कली से गौण स्रोतों के जरिए यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर के घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त आंकड़ों में यूरोपीय संघ में संबद्ध वस्तु के लिए समायोजनों के साथ, के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया था ।

61. प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य *** डालर/मी.टन संदर्भित किया है ।

ख. निर्यात कीमत

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा डीजीसीआई एंड एस से एकत्रित किये गये आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के व्ययों और अंतर्रेशीय भाड़े के लिये क्रमशः**** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी की सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया है जिन पर कारखाना द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए विचार किया गया है ।

एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य**** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित किया गया है।

इंडोनेशिया

क. सामान्य मूल्य

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली द्वारा उत्तर नहीं दिया है और प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद पाटन और क्षति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ नहीं की थी। प्राधिकारी ने इस असहयोग को ध्यान में रखते हुए नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन्डोनेशिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसलिए प्राधिकारी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अलकाली के द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में दी गई घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये इन्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के लिये समायोजन के साथ सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था।

अतः इंडोनेशिया के लिये सामान्य मूल्य **** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित की गई है।

ख. निर्यात कीमत

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा डीजीसीआई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया। याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के व्ययों और अंतर्देशीय भाड़े के लिये क्रमशः**** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी की सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया है जिन पर कारखाना द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए विचार किया गया था।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत**** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित की गई।

चाइनीज ताइपे

क. सामान्य मूल्य

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चाइनीज ताइपे से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली द्वारा उत्तर नहीं दिया है और प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद पाटन और क्षति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ नहीं प्रस्तुत की थीं। प्राधिकारी ने इस असहयोग को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चाइनीज ताइपे के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थात् क्लोर अलकाली के द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा चीनी ताइपे के घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत संबंधी आंकड़ों के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये चाइनीज ताइपे में संबद्ध वस्तुओं के लिये समायोजन के साथ सामान्य मूल्य का निर्धारण किया।

अतः चाइनीज ताइपे के लिये सामान्य मूल्य **** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित की गई है।

ख. निर्यात कीमत

66. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जनवरी-जुलाई 2002 की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त कारोबार आंकड़े, ताइवान से किसी भी आयात को नहीं दर्शा रहे हैं, जबकि मैसर्स नालको जो कि एक सहयोग करने वाला आयातक है, ने अप्रैल, 2002 तक चाइनीज ताइपे से 26189 मी० टन की सीमा तक आयात दर्शाये हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया वह साक्ष्य, जो प्रस्ताव को निर्दिष्ट करता है, जांचावधि के दौरान भारत में आयातकों द्वारा भी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मैसर्स नालको ने 8 जुलाई, 2000 को निविदा दी थी और मूलय की बोली 13 अगस्त, 2002 को खोली गई थी और कास्टिक सोडा की आपूर्ति के ए ताइवान मूल के दो विदेशी पक्षों को आर्डर दिए गए थे। 151 अमेरीकी डालर प्रति मी० टन की दर पर मैसर्स निशो हवाई को 30000 मी० टन और 174 अमेरीकी डालर प्रति मी० टन की दर पर मैसर्स अंगल्फ पालीमर्स एण्ड केमिकल्स को 55000 मी० टन के लिए आर्डर दिए गए थे। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री की तिथि: संविदा, क्य आदेश, आदेश पुष्टिकरण अथवा बीजक की वह कोई भी तिथि हो

सकती है। जो कोई भी बिक्री की मेटीरियल टर्मों को स्थापित करती हो। याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दी गई सूचना और उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने भारत को किए गए शिपमेंट से संबंधित निर्यात मूल्य को **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, निर्दिष्ट किया है। याचिकाकर्त्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के व्ययों और अंतर्रेशीय भाड़े के लिये क्रमशः**** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी, **** अमेरिकी डालर/डीएमटी और **** अमेरिकी डालर/डीएमटी की सीमा तक समायोजनों का दावा भी किया।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत**** अमेरिकी डालर/डीएमटी संदर्भित किया गया है।

छ. पाटन - सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना:

67. तुलना से संबंधित नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है :-

68. 'पाटन के मार्जिन का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी, निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेंगे। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर और सामान्यतया एक्स-वर्क्स स्तर पर और जहां तक संभव हो लगभग उसी समय की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण आधार पर उन अन्तरों के लिए उचित छूट दी जाएगी जिनसे बिक्री की शर्तों, कर प्रणाली, व्यापार के स्तरों, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अन्तरों और किसी अन्य अन्तरों, जो मूल्य की तुलनात्मकता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, सहित मूल्य की तुलनात्मकता प्रभावित होती हो।'

69. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली अनुबंध-I में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की सुसंगत नीति का अनुसरण किया है। ऊपर यथा इंगित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों के आधार पर प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका के अनुसार संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के मामले में पाटन मार्जिनों का मूल्यांकन किया था :

निर्यातकों/आयातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्न प्रकार बैठता है:-

क्र.सं.	देश/निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य(डालर/एम.टी.)	एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य (डालर/एम.टी.)	ई.पी.के % के रूप में पाटन मार्जिन
1	यूरोपीय संघ(फास को छोड़कर) सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	124.97%
2	इण्डोनेशिया सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	99.76%
3	चाइनीज ताइपे सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	89.95%

उपर्युक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध:

70. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II में दिए गए क्षति निर्धारण के सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है कि :

- क्षति के निर्धारण में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच निहित होगी (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान प्रकार की वस्तु के लिए घरेलू बाजा में मूल्यों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) इस प्रकार के उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामस्वरूप प्रभाव ।
- पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए कथित प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो अचर पद में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । मूल्यों के पाटित आयातों के संबंध में जैसाकि नियम 19(2) में उल्लूत किया है निर्दिष्ट प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्यों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में काफी कमी हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव, अन्यथा, मूल्यों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने के लिए है अथवा मूल्य में अन्यथा होने वाली महत्वपूर्ण वृद्धि को रोकने के लिए है । भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उक्त नियमों के अनुबंध-II(iv) के अनुसार उत्पादन,

क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया है।

क्षति का संचयी मूल्यांकन

71. उक्त नियम 11 के अंतर्गत अनुबंध-II(iii) आगे स्पष्ट करता है कि¹ ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी जांच का जा रही हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन तब करेंगे जब वह यह निर्धारण करते हैं कि प्रत्येक देश से आयात के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2% से अधिक व्यक्त किया गया हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का प्रत्येक देश से 3% हो अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3% से कम हो और आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिरप्ति की स्थितियों की दृष्टि से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित हो।

मै0 नाल्को के विचार:

72. नाल्को ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता की कथित एकमात्र शिकायत 8 जुलाई, 2002 को 11,500 मी. टन के लिए चलाई गई नाल्को निविदा को गंवान के कारण है। अतः माननीय प्राधिकारी द्वारा समान उत्पाद, पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के मुद्दों पर निर्णय लेते समय सिर्फ नाल्को मांग की विशिष्टता पर विचार किया जाना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि एल्युमिना के किसी अन्य विनिर्माता की तरह नाल्को मात्र लाई कॉस्टिक सोडा, न कि ठोस और फ्लेक्स क प्रयोग करता है। अतः माननीय प्राधिकारी द्वारा पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के मुद्दों पर विचार करते समय मात्र लाई कॉस्टिक सोडा की उत्पादन लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

73. नाल्को ने आगे निवेदन किया है कि निविदा के अंतर्गत मात्र 7000 मी0 टन का आयात किया गया है जो कि देश में कुल मांग, जो याचिकाकर्ता के खुद के प्रस्तुतीकरण के अनुसार लगभग 15,55,200 मी. टन है, का एक बहुत छोटा हिस्सा बनता है। आयातिक मात्रा देश में कॉस्टिक सोडा की कुल मांग का कुल 4.5% होती है।

74. क्षति का निर्धारण कॉस्टिक और क्लोरीन दोनों, न कि सिर्फ कॉस्टिक, से होने वाली आय पर विचार करने के पश्चात् कियाजाना चाहिए। क्लोर एल्कली कीमत सार रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि जब उत्तरी अमरीका में जुलाई, 2002 में कॉस्टिक ठेका कीमत 80-100 अमरीकी डालर डीएसटी एफओबी की रेंज में थी, क्लोरीन ठेका कीमत 235 अमरीकी डालर प्रति एसटी की रेंज में थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कीमत अंतर के कारण यदि उत्पादन लागत तथा आय पर अलग-अलग विचार किया जाता है, जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो इससे विकृतकारी दृष्टिकोण मिलता है। अतः यह निर्धारित करने के लिए कि विनिर्माताओं द्वारा कोई पाटन किया जा रहा है, कॉस्टिक तथा क्लोरीन से कुल आय पर विचार किया जाना चाहिए। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दोनों उत्पादों का साथ-साथ विनिर्माण किए जाने के कारण विनिर्माता किसी एक उत्पाद के बदले कॉस्टिक तथा क्लोरीन की कुल आय में रुचि लेता है।

75. नाल्को इसका आभार मानता है कि माननीय प्राधिकारी ने इस तथ्य के बारे में कि क्षतिरहित कीमत के किसी निर्धारण के लिए कॉस्टिक सोडा के उत्पादन के समय उत्पन्न होने वाले बहुमूल्य सह-उत्पाद क्लोरीन के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, उसके दावे को स्वीकार किया है। नाल्को एतदद्वारा 10 मार्च, 203 के अपने अनुरोधों में निर्दिष्ट अपने दावों को दोहराता है जिसमें कॉस्टिक सोडा तथा क्लोरीन की लागतों के लिए गणना प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक दिया गया है और जिसकी अन्तर्वस्तु को संक्षिप्तता के कारण यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

76. यह निवेदन किया गया है कि भारत में कॉस्टिक सोडा की उच्च उत्पादन लागत का कारण देश में विद्युत की उच्च लागत का होना है जो कि एक अनिवार्य निवेश है। क्षति रहित कीमत के किसी निर्धारण के लिए माननीय प्राधिकारी द्वारा क्लोरीन के संबंध में विद्युत की उच्च लागत तथा भारत में घरेलू विनिर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली अपर्याप्त भंडारण प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए।

77. यह निवेदन किया गया है कि सामान्य मूल्य निकालने के लिए क्लोर एल्कली रिपोर्ट को आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। तथापि, याचिका में निर्दिष्ट दरों से उस मास का पता नहीं चलता है जिसके लिए उन्हें लिया गया है। इससे नाल्को के विरुद्ध प्रारंभ किए गए कथित मामले का उत्तर देने की उसकी क्षमता पर अत्यधिक रोक लगी है। इसके अतिरिक्त, यह सादर निवेदन किया गया है कि चूंकि

वर्तमान जांच को प्रेरित करने वाली एक मात्र घटना नाल्को निविदा है, अतः सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सबसे उचित अवधि निविदा को अंतिम रूप देते समय बाजार में प्रचलित दरें होंगी । कॉस्टिक सोडा तथा क्लोरीन बाजारों में कीमत अस्थिरता के कारण यह उचित होता । इसके अतिरिक्त, कॉस्टिक सोडा की उच्च उत्पादन लागत का कारण विद्युत, जो कॉस्टिक सोडा के उत्पादन के लिए एक आवश्यक मूलभूत निवेश है, की उच्च लागत है ।

घरेलू उद्योग के विचार:

78. याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि याचिका में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि जांच नाल्को पर केन्द्रित है और शुल्क मात्र नाल्को द्वारा किए गए आयातों पर लगाया जाना चाहिए । जहाँ तक नाल्को द्वारा प्रचलित निविदा को गंवाने का संबंध है, यह एक तथ्य है कि घरेलू उद्योग ने निविदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाटित आयातों के कारण गंवाया है । इसके अतिरिक्त अन्य आयातक/उपभोक्ता हैं जिन्होंने संबद्ध देशों से आयातित कॉस्टिक सोडा की अत्यधिक मात्रा का उपभोग किया है । अतः, यह कहना भ्रामक है कि संपूर्ण जांच नाल्को पर केन्द्रित है । घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि जांच नाल्को पर केन्द्रित है और मात्र नाल्को द्वारा किए गए आयातों पर शुल्क लगाया जाना चाहिए । नाल्को का यह तर्क उसका अपना बनाया हुआ है ।

79. जहाँ तक नाल्को द्वारा प्रचलित निविदा को गंवाने का प्रश्न है, यह एक तथ्य है कि घरेलू उद्योग ने निविदा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पाटित आयातों के कारण गंवाया है । नाल्को के अतिरिक्त अन्य आयातक/उपभोक्ता हैं, जिन्होंने संबद्ध देशों से आयातित कॉस्टिक सोडा की अत्यधिक मात्रा का उपभोग किया है । अतः, यह कहना भ्रामक है कि पूरी जांच नाल्को पर केन्द्रित है ।

80. यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि घरेलू उद्योग ने स्वयं विभिन्न रूपों में एंटी डंपिंग को पसंद किया है ताकि ऐसे मामलों में जब निर्यात कीमत उचित है तो पाटनरोधी शुल्क न लिया जाए ।

81. नाल्को भारतमें एल्युमिनियम का एकमात्र उत्पादक नहीं है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाल्को के तर्क को पाटन की मूलभूत परिभाषा का भी समर्थन प्राप्त नहीं है । पाटन तभी होगा जब भारत में निर्यात कीमत घरेलू कीमत से कम हो । ऐसे मामले

में, नाल्को का यह विश्वास करना कि एल्युमीनियम के अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को सामग्री समान पाटित कीमतों पर प्राप्त होती है, उसकी भ्रांति है।

82. तथ्य यह है कि नाल्को ने भारतीय उत्पादकों पर इसके प्रभाव की पूर्ण उपेक्षा करते हुए कॉस्टिक सोडा के आयातों का सहारा लेने के सभी संभव प्रयास किए हैं। वस्तुतः नाल्को को कॉस्टिक सोडा के यही निर्यातक नाल्को के साथ अपनी वचनबद्धता से पीछे हट गए हैं और भारतीय उत्पादक कंपनी की सहायता के लिए आगे आए थे।

83. क्रिस इन्फैक ने कॉस्टिक सोडा तथा क्लोरीन से होने वाली कुल प्राप्ति से नमक तथा विद्युत लागत को घटाकर परिवर्तनीय मार्जिन परिकलित किया है। अतः नाल्को ने यह अनुमान लगाया है कि कॉस्टिक सोडा उत्पादकों द्वारा लगाई जाने वाली सारी लागत नमक तथा विद्युत के कारण है और कॉस्टिक सोडा के उत्पादन तथा बिक्री कोई और लागत शामिल नहीं होती है। नाल्को ने सुविधापूर्वक अन्य कच्ची सामग्रियों, वेतन तथा भत्ते, मरम्मत तथा रख-रखाव, उपभोज्य, अन्य विनिर्माण संबंधी ऊपरी व्यय, मूल्य हास, वित्त, प्रशासन, बिक्री तथा प्रशासनिक आदि के कारण विश्व भर में कॉस्टिक सोडा के किसी भी उत्पादक द्वारा लगाई जाने वाली लागत की उपेक्षा कर दी है। तथ्य यह है कि इन कारणों से लगाई गई लागत उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।

84. क्रिस इन्फैक रिपोर्ट को अधिक से अधिक अपनी अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा प्राप्त योगदान का संदर्भ देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यह रिपोर्ट भी सुझाव देती है कि उद्योग के लिए परिवर्तनशील मार्जिनों में पिछले वर्षों की तुलना में काफी गिरावट आई थी। अतः, क्रिस इन्फैक रिपोर्ट अधिक से अधिक यह स्थापित करती है कि घरेलू उद्योग के लिए मार्जिनों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि क्रिस इन्फैक द्वारा इन परिवर्तनशील मार्जिनों का निर्धारण कॉस्टिक सोडा तथा क्लोरीन से आया पर विचार करने के बाद किया जाता है। अतः, संयुक्त आय के आधार पर भीघरेलू उद्योग के मार्जिनों में गिरावट आई है।

85. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि निविदा का एक हिस्सा घरेलू उत्पादकों को भी आबंटित किया गया था। तथापि, घरेलू उद्योग के पास नाल्को तथा भारतीय मांग की सारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है। नाल्को का यह तर्क कि घरेलू

उद्योग को लाभ हो रहा है, जानकारी और तथ्यों की जांच के बिना है। याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उन पर विश्वास किया गया है।

86. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। यह स्पष्ट है कि :

(क) संबद्ध देशों से आयातों में सम्पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आयात, जो पहले नगण्य थे, बहुत कम अवधि में उच्च स्तर तक पहुंच गए जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि निर्यातक पाटन का आश्रय लेने के द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वर्तमान जांच अवधि में आयातों की मात्रा 1980 से सभी पुराने स्तरों को पार कर गई।

(ख) संबद्ध देशों से आयातों में भारत में उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है।

(ग) संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में भारत में कुल आयातों की तुलना में वृद्धि हुई है।

(घ) भारत में उत्पाद की मांग में सबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

(ङ.) घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि एक के बाद एक कई देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप है।

(च) जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है।

(छ) घरेलू उद्योग में पाटित आयातों और नाल्को निविदाओं के ऑर्डर को गंवाने के कारण अत्यधिक बिक्री मात्रा गंवाई है।

(ज) यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने में असमर्थ रहा है।

(झ) संबद्ध देशों की निर्यात कीमत में काफी गिरावट आई है, परिणामस्वरूप पहुंचमूल्य में गिरावट आई है। इससे भारतीय बाजार में अत्यधिक कीमत कटौती

(य.) कॉस्टिक सोडा का बाजार कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है, जहां एक छोटी राशि के अंतर का परिणाम बिक्रियों की अत्यधिक हानि होगा। वस्तुतः, इस उद्योग द्वारा प्रभावित कीमत वृद्धि/कटौती कई बार बहुत कम रही है। अतः, आयातों के पहुंच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में किसी अंतर को उपभोक्ता काफी लाभप्रद पाते हैं।

(ट) आयातों का पहुंच मूल्य उद्योग की उत्पादन लागत तथा क्षति-रहित कीमत से कम है। अतः, आयातों का घरेलू बाजार की कीमतों पर अत्यधिक अवमूल्यनकारी/हासकारी प्रभाव हो रहा है।

(ठ) कॉस्टिक सोडा उद्योग ने देश में काफी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया है। उद्योग की किसी रूणता का नकेवल प्रत्यक्ष रोजगार पर बल्कि देश में काफी बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि कंपनियों में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्मचारियों को बहाल रखने की नीति है, तथापि लगातार घाटे के कारण कर्मचारी हतोत्साहित हैं तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं।

(ड) घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में कॉस्टिक सोडा की बिक्री की प्रत्येक इकाई से वित्तीय घाटा हो रहा है। नए पाटित स्रोतों को अपनाए जाने के कारण, कई देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद वित्तीय घाटे हो रहे हैं।

(ढ) घरेलू उद्योग की माल सूची जो पहले बढ़ रही थी, में जांच अवधि में गिरावट आई है।

(ण) उत्पादन में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ी है।

(त) घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय ऋणात्मक बनी हुई है।

(थ) घरेलू उद्योग के कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि हुई है। घाटे की स्थिति में भी प्रचलित कानूनों के कारण घरेलू उद्योग के पास भत्तों को बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त, भत्तों में किसी गिरावट का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(द) जैसाकि पहले निवेदन किया गया था, घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है। घरेलू उद्योग को हो रहे लगातार घाटे के परिणामस्वरूप कंपनियों के नकद प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ध) घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के अतिरिक्त पाटित आयातों के कारण उन्हें और क्षति का खतरा है।

87. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में काफी अधिक दर से वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को और क्षति होने का खतरा है।

88. संबद्ध देशों के विनिर्माताओं तथा निर्यातकों के पास काफी अधिक क्षमता और स्टॉक है ।

89. घरेलू उद्योग की गंभीर चिंता उस कीमत के बारे में है जिस पर उत्पादका आयात हो रहा है । जिस कीमत पर सामग्री का निर्यात हो रहा है, वह पाटित कीमत है । इसके अतिरिक्त, बाजार में सामग्री का प्रवेश घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम कीमतों पर हो रहा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण करते समय क्षति के संबंध में सभी संकेतकों पर विचार किया है । इसमें सभी संगत तथ्य अर्थात् पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार की कीमत पर उनका प्रभाव और घरेलू उत्पादकों पर उसका उत्तरवर्ती प्रभव, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति आदि शामिल हैं । घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए इष्टतम उत्पादन लागत पर विचार किया, जो विनियामक सर्वोत्तम उपभोग प्रतिमान का और जांच अवधि के दौरान कच्चे माल, जिनका प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए होता है, की कीमत का भी ध्यान रखेगी ।

91. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक का पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के % के रूप में अभित्यक्त 2% की सीमा से अधिक है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देश से आयातों की मात्राएं न्यूनतम से अधिक हैं । चूंकि संबद्धदेशों से आयातों की आपस में और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है, अतः आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा । अतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के संचयी मूल्यांकन का प्रस्ताव करते हैं ।

92. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उक्त नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन इत्यादि ।

93. निम्नलिखित मानदंड यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है:

व्यौरा	इकाई	1990-00	2000-01	2001-02	जनवरी-सितंकर 02	वार्षिक
बिक्री	सूचीबद्ध	100.00	99.37	100.58	100.71	100.71
उत्पादन की लागत	सूचीबद्ध	100.00	93.05	98.47	86.83	86.83
बिक्री मूल्य	सूचीबद्ध	100.00	116.61	130.40	99.26	99.26
लाभ/हानि	सूचीबद्ध	-100.00	116.61	130.40	99.26	99.26
क्षमता		809800	809800	822300	822300	822300
प्रवृत्ति(सूचीबद्ध)		100	100	101.54	101.54	101.54
क्षमताउपयोग		89.96%	91.57%	90.01%	70.29%	93.72%
उत्पादन	मी.टन	728526	741555	740192	578000	770667
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	101.79	101.60	105.78	105.78
बाजार हिस्सा(आयात)						
यूरोपीय संघ	मी.टन	298	19964	173	12746	19119
ताइवान	मी.टन	0	19033	327	85000	127500
इंडोनेशिया	मी.टन	14860	0	4972	26031	39047
संबद्ध देश	मी.टन	151598	38997	5472	123777	185666
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	257.27	36.10	816.58	1224.87
अन्य देश	मी.टन	81921	40434	38781	74588	99450
कुल आयात	मी.टन	97079	79431	44253	198365	285116
आयातों में बाजार हिस्सा						
यूरोपीय संघ	%	0.31	25.13	0.39	6.43	6.71
ताइवान	%	0.00	23.96	0.74	42.85	44.72
इंडोनेशिया	%	15.31	0.00	11.24	13.12	13.69
संबद्ध देश	%	15.61	49.10	12.37	62.40	65.12
अन्य देश	%	84.39	50.90	87.63	37.60	34.88
मांग में						
व्यापारिक मांग	मी.टन	1391534	1409949	1406129	1161611	1548815
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	101.32	101.05	111.30	111.30
कैप्टिव खपत	मी.टन	202260	233726	209728	172479	229972
मांग	मी.टन	1593794	1643675	1615857	1334090	1778787
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	103.13	101.38	111.61	111.61
मांग में बाजार हिस्सा						

कॉटिव सहित घरेलू उद्योग	%	45.27	45.62	45.30	42.33	42.33
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	100.76	100.07	93.50	93.50
कॉटिव सहित घरेलू उद्योग	%	32.58	31.40	32.32	29.40	29.40
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	96.36	99.21	90.24	90.24
अन्य उत्पादक	%	48.64	49.55	51.96	42.80	41.64
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	101.08	106.83	88.00	85.62
संबद्ध देश	%	0.95	2.37	0.34	9.28	10.44
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	249.46	35.61	975.54	1097.48
अन्य देश	%	5.14	2.46	2.40	5.59	5.59
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	47.86	46.69	108.77	108.77
बौरा						
उत्पादकता (प्रति कर्मचारी)						
कर्मचारी	सूचीबद्ध	100.00	98.46	97.22	127.36	95.52
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सूचीबद्ध	100.00	103.38	104.51	110.74	110.74
निवेश पर आयत						
लगाई गई पूँजी पर आय	%	-12.58	-5.88	-4.60	-7.81	-7.81
माल सूची	मी.टन	6511	8233	15080	21652	21652
प्रवृत्ति		100	126.44	231.60	332.53	332.53
कर्मचारी	संख्या	4421	4353	4298	4223	4223
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98.46	97.22	127.36	95.52
मजदूरी	लाख में	5649.17	5684.45	6603.55	4827.75	6437.00
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100.62	116.89	113.95	113.95

पारित आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा

94. संबद्ध देशों से कास्टिक सोडा का आयात में (i) समग्र रूप से: (ii) उत्पादन के संबंध में: और (iii) भारत में खपत के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जबकि आयात मुख्यतः अनेक देशों से होते रहे हैं, लेकिन ईयू (फ्रांस को छोड़कर), इण्डोनेशिया और ताइवान से हुए आयातों के हिस्से में भारत में मांग के संबंध में जांच अवधि के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा

2001-2002 में 12.37% से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकी) के दौरान 62.40% हो गया है। आयात अन्य अनेक स्रोतों से हो रहे हैं लेकिन वे आयात या तो न्यूनतम से कम हैं या उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयात बढ़ा है।

95. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में यह वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई है कि मांग भी बढ़ी है। संबद्ध वस्तु के आयात की वृद्धि की दर, कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादन और मांग में वृद्धि की दर बहुत अधिक है।

96. याचिकाकर्ता कंपनियां अपनी कीमतों का निर्धारण प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर करती हैं। बाजार कीमतें पाटित आयातों की निम्नतर कीमतों द्वारा संचालित होती थी क्योंकि पाटित आयातों का हिस्सा 2001-02 में 12.37% से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकी) के दौरान 62.40% हो गया है।

97. यद्यपि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा में मामूली वृद्धि हुई है, तथापि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में भारी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग पाटित आयातों की बराबरी करने के लिए अपनी बिक्री कीमत नहीं घटा सका। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की तुलना में इतनी कम है कि घरेलू उद्योग आयातित संबद्ध वस्तुओं की कीमत के बराबर अपनी कीमतें घटाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि विद्यमान स्थिति में घरेलू उद्योग लाभ और पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार, दोनों गां चुका है।

मांग में बाजार हिस्सा

98. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा कैप्टिव सहित 2001-2002 में 45.30% से घटकर जांच अवधि (वार्षिक) में 42.33% हो गया है जबकि मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर) 2001-2002 में 32.32% से घटकर इसी अवधि में 29.40% हो गया है। अन्य उत्पादकों ने भी मांग में महत्वपूर्ण रूप से अपना हिस्सा मोटे तौर पर 10% खो दिया है जिसका स्थान संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने ले लिया है। अन्य देशों से आयातों का हिस्सा भी घरेलू उद्योग को प्रभावित किए/क्षति पहुंचाये बिना 3% बढ़ा है क्योंकि ये आयात गैर-पाटित कीमतों पर आ रहे हैं। सामान्यतः मांग 2001-2002 में 101.38 से बढ़कर जांच अवधि में 111.61 हो गई

है, तथापि, मांग में इस वृद्धि पर अधिकतर चीन से पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को संबद्ध देशों से कास्टिक सोडा के पाटित आयातों के कारण विस्थापित कर दिया है।

माल सूची तथा ठेकों को गंवाने के संबंधित साक्ष्य

99. प्राधिकारी नोट दर्ते हैं कि माल-सूची स्टॉक 2001-2002 में 15080 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 121652 मीट्रिक टन हो गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच अवधि (वार्षिक) में स्टॉक में वृद्धि की प्रवृत्ति और बाजार में विस्थापन का कारण संबद्ध देशों से पाटित आयात है।

100. यह दावा किया जाता रहा है कि निर्यात मूल्य में कमी के कारण घरेलू उद्योग को विक्रय मूल्य को निर्यात मूल्य के अनुकूल रखने और प्रतिस्पर्धा के स्तर पर विक्रय मूल्य रखने पर बाध्य होना पड़ रहा है। इस स्थिति में घरेलू उद्योग सीमान्त लागत वसूल करने में समर्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी दावा किया जाता है कि घरेलू उद्योग इतनी कम कीमत पर कास्टिक सोडा बेचने में असमर्थ है जिससे ठेकों को गंवाना पड़ रहा है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग को घाटे पर उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

101. क्षति के साक्ष्य के अनक मानदण्ड हैं, क्या वर्तमान पाटित कीमतों पर आयातों की अनुगति दी जानी चाहिए। संबद्ध देशों से जांचावधि के दौरान आयातों की वृद्धि दर और घरेलू उद्योग के लगां में तदनुरूपी गिरावट ऐसे मानदण्ड हैं जिनसे घरेलू उद्योग लगां हो रही क्षति रूपरूप से मालूम होती है। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह देखा गया है कि संबद्ध वर्सु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली पर पाटन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। रायिकाफर्टा को बाजार के अपने हिस्से को बनाए रखने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वर्सु की कम कीमत और पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से अत्यधिक कीमत कटौती के साक्ष्य की जानकारी मिलती है।

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने कम कीमत पर यह बिक्री कीमत की सीमा निर्धारित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की उचित बिक्री कीमत का परिकलन किया है और इसकी तुलना पहुंच कीमत के साथ की है। इस विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि कम कीमत पर बिक्री होने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का अत्यधिक हासकारी/अवभूत्यनकारी प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि पाटित आयातों के मद्देनजर घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों की जांच से यह प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की बिक्री से घरेलू उद्योग को समग्र रूप से क्षति हुई थी। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की सीमा निर्धारित की है और यह माना है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के कारण नुकसान हुआ है।

रोजगार

103. घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर पिछले तीन वर्षों से लगातार घट रहा है और सूचकांक 1999-2000 में 100 से घटकर जांच अवधि (वार्षिकी) के दौरान 95.52 तक आ गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार में इस परिवर्तन का कारण घरेलू उद्योग को भारी हानि तथा दक्षता और उत्पादकता को अधिकतम बनाने के लिए किए गए लागत कटौती उपाय हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार के स्तर में इस अवनति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी।

104. कर्मचारियों की संख्या में कटौती के बावजूद भी घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार नहीं हुआ है। तथापि, यह भी देखा गया है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन बढ़ है, जबकि प्रतिदिन उत्पादन में काफी गिरावट आई है।

लाभप्रदता

105. उत्पादन की इकाई लागत 1999-2000 में 100 से घटकर वार्षिक जांच अवधि में 86.83 हो गई है जबकि इकाई विक्रय कीमत भी 1999-2000 में 100 से सीमान्ततः घटकर वार्षिक जांच अवधि में 99.26 रह गई है। इकाई विक्रय

कीमत, उत्पादन लागत के अनुपात में नहीं घटी है जिससे वित्तीय घाटे में सुधार होता है जो घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अभी भी पर्याप्त सहायता नहीं करता है। घरेलू उद्योग का इस तथ्य के कारण घाटा सहना पड़ रहा है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण, बाजार पर पकड़ बनाने के लिए घरेलू उद्योग को विक्रय कीमतों को उसकी उत्पादन की लागत से कम करने पर बाध्य होना पड़ रहा है। उद्योग को कम विक्रय कीमत के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है जिससे उत्पादन की लागत की वसूली नहीं हो पा रही है तथा परिणामतः वित्तीय घाटा हो रहा है।

106. जहां बिक्री की लागत, उत्पादन मूल्य और बिक्री मूल्य भी बढ़े हैं, वहीं बिक्री की लागत में वृद्धि बिक्री मूल्य में वृद्धि से अधिक है। इससे सीधे तौर पर घरेलू उद्योग के लाभ में कमी हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है, तथापि, यह पाया गया है कि उत्पादन और बिक्री मात्रा में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी अवनति हुई है। अतः उत्पादन और बिक्री मात्रा में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को इसके लाभों में वृद्धि करने में सहायता नहीं की है।

निवेश में वृद्धि और आय

107. उत्पाद की मांग बढ़ी है, यद्यपि घरेलू उद्योग की वृद्धि में काफी गिरावट आई है। देश में मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद आयातघरेलू उद्योग की वृद्धि को धीमा कर रहे हैं। यह दावा किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग लक्ष्य प्राप्त करने अथवा यदि संबद्ध देशों से पाटित आयातों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते तो बाजार से पूंजी प्राप्त करने के प्रति शंकालु है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए नये निवेशों की योजना बनाना कठिन होगा।

108. घरेलू उद्योग का नकद लाभ जांच अवधि के दौरान घटा जिससे घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

109. इसके अतिरिक्त, मजदूरी में वृद्धि से बिक्री की लागत में अतिरिक्त वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग अपने लाभों को कायम कहीं रख सका। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास देश में प्रचलित विनियमों के तहत मजदूरी में वृद्धि

करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है । तथापि, बढ़ी हुई मजदूरी से लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग इसके अनुपात में कीमतें बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं ।

संचयी आकलन

110. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रत्येक संबद्ध देशसे पाटन का मार्जिन 2% की सीमा से अधिक था जिसे निर्यात मूल्य की प्रतिशतता में व्यक्त किया गया है । इसके साथ ही, प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है । आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन किया जाना उचित होगा क्योंकि संबद्ध देशों से किए जाने वाले निर्यात भारतमें सीधे ही एक दूसरे से और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ नियमावली के अनुबंध II में दिए गए संचयी आकलन से मिलती हैं यथा (1) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है: (2) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा निर्धारित सीमा से अधिक है: और (3) आयातित सामग्री सीधे तौर पर घरेलू सामग्री से प्रतिस्पर्धा करती है । इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संगत कारक संचयी और समग्र रूप ये यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

111. क्षति का खतरा के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियम निम्न प्रकार से उल्लेख करते हैं :-

‘ भौतिक क्षति का खतरा के निर्धारण को तथ्यों पर आधारित किया जाएगा न कि केवल आरोप, अनुमान और दूर की संभावनाओं पर । परिस्थितियों में बदलाव को, जो कि एक ऐसी स्थिति सृजित करती हों जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए । क्षति का खतरा के निर्धारण करने में प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के तथ्यों और निम्न को ध्यान में रखेंगे :-

(क) भारत में पाटित आयातों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि जो काफी बढ़े हुए आयातों की संभावनाओं को दर्शाती हो ;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को समा लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजार में काफी बढ़ हुए आयातों की संभावनाओं को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में आई काफी वृद्धि को ।

(ग) क्या आयात उन मूल्यों पर होने जा रहे हैं जो घरेलू मूल्यों पर काफी निराशाजनक और दबावकारी प्रभाव डालेंगे और जिससे और आयात किए जाने की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी ; और

(घ) वस्तु की भंडारणत स्थिति की जांच की जा रही है ।

112. वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में प्राधिकारी ने नोट किया कि जांचाधीन अवधि के दौरान पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अर्थात् 2001-2002 के दौरान 5472 की तुलना में 123777 मी० टन । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से ये आयात, घरेलू उद्योग के मूल्यों में काफी कमी करते हैं जिससे घरेलू उद्योग को अलाभकारी मूल्यों पर बिक्री करनी पड़ती है । इसके अलावा सामग्री एक ऐसे मूल्य पर आ रही है जो घरेलू मूल्य के बिक्री मूल्य से काफी कम है और यदि घरेलू उद्योग इस मूल्य पर बिक्री करना शुरू करता है तो इससे घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानि होगी । मैसर्स नालकों द्वारा संबद्ध देशों के हक में दिये गये आदेश से भी मात्रात्मक रूप से घरेलू उद्योग को काफी हानि होगी ।

113. इन देशों में भारी उत्पादन के मद्देनजर इन स्रोतों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने की भी संभावना है । यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जिसे यदि इसको पाटित कीमतों पर भारत को निर्यातों के लिए उपयोग किया जाता है तो यह घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए चिन्ता का विषय हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि आयात पाटित कीमतों पर इसी गति से जारी रहते हैं तो अत्यधिक कीमत कटौती की मौजूदगी के कारण आयातों में बहुत अधिक वृद्धि होगी ।

114. वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन और संबद्ध देशों के मूल के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के संदर्भ में देखा जाना अपेक्षित है । घरेलू उद्योग को पहले सऊदी अरब, जापान, ईरान, फ्रांस, कतर, कोरिया गणराज्य और चीन से वास्तविक क्षति हुई हुई है जिनके लिए पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

115. कुछ स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से विशाल भारतीय बाजार उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल लाभजनक बन गया है जिनके पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं या पर्याप्त घरेलू मांग नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय बाजार में क्षति का खतरा एक दूरस्थ संभावना का अनुमान नहीं है बल्कि वास्तविक तथा सन्तुलित है।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की वृद्धि दर और घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति और लाभों में तदनुरूपी गिरावट वे मापदंड हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति को साफ तौर पर प्रदर्शित करते हैं। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के अंधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान क्षति उठाई है और यह आगे भी क्षति के खतरे का सामना कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति के खतरे का सामना कर रहा है।

117. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध उत्पादों से बिक्री की प्राप्ति पर उचित तौर पर विचार करके विभिन्न घरेलू उत्पादकों के लिये गैर क्षतिकारक मूल्य का आंकलन किया गया है। इसके अलावा, अक्षमताओं को दूर करने में प्राधिकारी ने कच्चे माल, उपयोगी वस्तुओं आदि के उपयोग के बारे में सबसे अच्छी पद्धतियों को मापदंड बनाया है।

118. उस क्षति के बारे में जो भारत में उत्पादन की अधिक लागत के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी नियमों के तहत यह कमतर शुल्क नियम है जिसे लागू किया जाता है। इसके अलावा, पाटन रोधी शुल्क किसी भी दशा में पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता।

119. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि सभी संबद्ध कारक संचयी और सामूहिक रूप से इस बात की पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति उठाई है। आयातों से वास्तविक क्षति का खतरा और भी उत्पन्न हो रहा है।

इ। कारणात्मक संबंधः

120. प्राधिकारी ने इस बात का निर्धारण करते समय कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई थी, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया:-

121. पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के भारी आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतों को अलाभकारी स्तर तक कम करने को बाध्य किया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत कटौती की स्थिति उत्पन्न हुई ।

122. संबद्ध देशों से आयातों ने भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतों को इस सीमा तक कम कर दिया कि घरेलू उद्योग अपनी पूरी उत्पादन लागत की वसूली नहीं कर सका और भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से उचित लाभ अर्जित नहीं कर सका ।

123. संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत कम करने के लिए बाध्य किया है जिससे इसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

124. इसलिए प्राधिकारी उपर्युक्त से यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात एक ऐसी कीमत पर किए गए हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं । इसके अलावा, भारत में आयात घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत से कम कीमत पर किए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने निवेश पर तर्कसंगत लाभ प्राप्त करने में असफल रहा है । ये मापदंड सामूहिक और संचयी रूप से इस बात के सूचक हैं कि याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठाई है और आगे भी वास्तविक क्षति का खतरा है ।

125. कुल खपत में पाटित आयातों की मात्रा का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 0.34% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 9.29% हो गया है । घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2000-01 में 45.30% से घटकर जांच अवधि में 42.33% रह गया है । पाटित आयात भारत में ऐसी कीमत पर आ रहे थे जिससे समान घरेलू उत्पाद की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हुई । पाटित आयातों की कीमतों ने समान घरेलू उत्पादों की

कीमतों को मन्दा तथा कम कर दिया । अतः मात्रा और कीमत दोनों पर पड़े प्रभाव की पुष्टि होती है ।

126. मांग में कोई कमी नहीं हुई है (बल्कि मांग बढ़ी हैं) । इसके अलावा, व्यापर प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रौद्योगिकी विकास जैसा कोई अन्य कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा सकता है । आयातों में निरपेक्ष रूप से आर भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से भी हुई वृद्धि के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बिक्रियों में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप देश में उत्पाद की मांग से घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आयी है । इसके अलावा, आयातों की कम कीमतों के कारण घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता को इष्टतम नहीं कर पाया ।

भारतीय उद्योग का हित और अन्य विषय

127. प्राधिकारी यह भी विचार रखते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य साधारणतया पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षतियों को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति की पुनर्बहाली हो सके, जो बात देश के आम हित में है ।

128. प्राधिकारी इस बात को भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु से विनिर्मित उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप यह इन उत्पादनों की सम्बन्धात्मक प्रतिस्पर्द्धाओं पर कुछ असर डाल सकता है, तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा इन पाटनरोधी उपायों से कम नहीं हो पाएगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को लागू करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा और इससे घरेलू उद्योग का हास रुकेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी ।

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय संबद्ध देशों से आयातों को किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं करेंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेंगे ।

130. प्राधिकारी ने उचित बिक्री कीमत के संबंध में केवल याचिकाकर्त्ताओं के निवेदनों पर विश्वास नहीं किया है, बल्कि प्राधिकारी ने कास्टिक सोडा के विभिन्न रूपों की लागत और विनिर्माण प्रक्रिया की मौके पर जांच और सत्यापन के लिए एक टीम को प्रतिनियुक्त किया है और भारत में घरेलू उद्योग के लिए कास्टिक सोडा की उचित बिक्री कीमत को विस्तृत रूप से अलग से परिकलित किया है ।

131. उपभोक्ताओं ने तर्क दिए हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कास्टिक सोडा के उपभोक्ताओं के लिए कम प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमतों में वृद्धि होगी और प्रयोक्ता उद्योग को हानि होगी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुचित प्रथाओं पर आधारित कीमत फायदे न्यायसंगत नहीं हैं और अन्त में उपभोक्ता के हित के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं ।

132. प्राधिकारी ने कास्टिक सोडा की उचित बिक्री के संबंध में केवल याचिकाकर्त्ताओं के निवेदनों पर विश्वास नहीं किया है, बल्कि प्राधिकारी ने मै0 नाल्को द्वारा एल्यूमिना के विनिर्माण में कास्टिक सोडा के उपयोग की मौके पर जांच और सत्यापन के लिए याचिकाकर्त्ताओं में से एक मै0 डी.सी.डब्ल्यू लि�0 जो समुद्र के माध्यम से रेलवे टैंक वैगन में कास्टिक सोडा के क्षारोदक घोल की आपूर्ति कर रहा है, की उपस्थिति में एक टीम को प्रतिनियुक्त किया । सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने नोट किया कि मै0 डी.सी.डब्ल्यू लि�0 ने उनको दिसम्बर, 2001 से फरवरी 2003 तक कास्टिक सोडा के क्षारोदक घोल की आपूर्ति नहीं की क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तावित की गई कीमतें किफायती नहीं थी, जबकि मार्च, 2003 से 38,500 मीट्रिक टन के लिए आदेश तर्कसंगत उचित कीमत पर स्वीकार किए गए हैं ।

अ. निष्कर्षः

133. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि :

- (i) भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात इनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।
- (ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और आगे भी क्षति के खतरे का सामना कर रहा है।
- (iii) संबद्ध देशों से आयातों ने संचयी रूप से क्षति पहुंचाई है।

134. घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से कास्टिक सोडा के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक मानते हैं। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन उपर्युक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है। प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की राशि को पाटन मार्जिन के समान या कम करने के सिफारिश करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर होगी। क्षति को निर्धारित करने के उद्देश्य से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना याचकाकर्ता कंपनियों की जांच अवधि के लिए निर्धारित भारित औसत गैर क्षतिकारी कीमत के साथ की गई है।

135. तदनुसार प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमा शुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत आने वाले कास्टिक सोडा के सभी आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए जो निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। पाटनरोधी शुल्क निम्न तालिका के कॉलम संख्या 9 में उल्लिखित राशि तथा प्रति मीटन आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा जो नीचे उल्लिखित संबद्ध क्षेत्रों/देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के अन्तर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर लागू होगा।

136. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9 के तहत लागे गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा ।

137. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी 8 जनवरी, 2003 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

138. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2003

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning import of Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France)—Final Findings.

No. 14/39/2002-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a petition from M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as petitioner) on behalf of the domestic industry, alleged dumping of Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) (hereinafter referred to as subject countries). The petition was supported by M/s DCW Limited, Mumbai, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Vadodara, Gujarat, M/s Search Chem Industries Limited, Mumbai, M/s Grasim Industries Ltd, Nagda, M.P., M/s SIEL Chemical Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals, Ltd., Jharkhand, M/s Jayshree Chemicals Limited, Orissa, M/s Andhra Sugars Limited, Tanaku, DCM Sriram, New Delhi, M/S Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara, M/S Standard Alkali, Mumbai and M/S DCM Sriram Consolidated Ltd., New Delhi.

ii) The Authority issued a public notice dated 8th October 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under custom Code 281511 and 281512 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 (28151101, 28151102 and 28151200 of ITC) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France)

iii) The cost of production of the domestic industry was also analysed to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) based on the information furnished by petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry. The cost of production data of the following companies were considered and examined appropriately:—

1. M/s DCW Limited, Mumbai
2. M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., Vadodara
3. M/s Search Chem. Industries Ltd., Mumbai
4. M/s Grasim Industries Ltd., Nagada (MP)
5. M/s. SIEL Chemicals Complex, Punjab
6. M/s Bihar Caustic & Chemicals Ltd.. Bihar
7. M/s Jayshree Chemicals Ltd, Orissa
8. M/s Andhra Sugars Ltd., Tanaku
9. M/s. Indian Petro Chemicals Corporation Ltd., Dahej

iv) The Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered necessary;

v) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification No. 14/39/2002-DGAD dated the 8th January, 2003 with regard to Anti Dumping investigations concerning imports of Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

vi) The Authority forwarded a copy of the Preliminary Findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter;

vii) The Authority also forwarded copy of the Preliminary Findings to the Embassies/High Commissions/Representatives of subject countries in New Delhi with a request to furnish their views on the Preliminary Findings;

viii) The Authority held a public hearing on 22nd April 2003 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, importers and exporters from subject countries. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions thus received from interested parties have been considered by Designated Authority in these finding;

ix) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7);

x) In accordance with Rule 16 of the Rules, upon the essential facts/basis considered for these findings, were disclosed to known interested parties and comments received on the same, have also been duly considered in these findings;

xi) Investigation was carried out for the period starting from 1st January, 2002 to 30th September, 2002.

xii) ******* in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION /LIKE ARTICLE

VIEW OF DOMESTIC INDUSTRY

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH. It is an Inorganic Chemical classified under Chapter 28 of the Custom Tariff Act. Caustic Soda produced by the domestic industry is like article to the Caustic Soda imported from subject countries within the meaning of anti dumping rules. Even though all three technologies are being used in India for manufacturing Caustic Soda, Mercury Cells and Membrane Cells technology are being widely used in India.

VIEW OF M/s. NALCO

M/s. NALCO has submitted that the Caustic Soda lye and solids/flakes are different products and cannot be treated as like product for the present investigation. It is submitted that the especially with respect to aluminium industry, lye Caustic Soda form is only used world over in the production of aluminium. Thus solids/flakes Caustic Soda is not and cannot be used in the production of aluminium and is not commercially substitutable for the Caustic Soda.

The difference between lye and solids arises on account of the former having a lower concentration of Caustic Soda than the latter which has a greater concentration of Caustic Soda. Therefore, it is submitted that solids/flakes and lye Caustic Soda cannot be treated as like product. Only liquid Caustic Soda should be considered for arriving at as whether there is a dumping and whether there is any injury to indigenous industries. The Caustic Soda liquid is completely different from Caustic Soda solid/flakes as it involves further manufacturing process thereby the cost of production is different. Their end use is different along with the market value, handling, storage and transportation etc.

M/s. NALCO submits that as the sole triggering for the investigation is the alleged loss of the NALCO tender, the product under consideration should be the product procured by the Tender. It is stated that the product procured by the Tender was lye Caustic Soda, which alone is used by NALCO and the aluminium industry the world over. It is submitted that considering the other forms of Caustic Soda has the effect of distorting the assessment of dumping undertaken by the Hon'ble Authority in the present investigation. NALCO respectfully submits that in accordance with the worldwide practice of the aluminium industry, aluminium manufacturers only procure lye caustic soda and do not procure solid caustic soda as procurement of the latter would lead to imposition of greater cost on the

manufactures, in addition to the diversion of resources from the main manufacturing activity into a subsidiary activity, namely, conversion of the solid caustic soda into lye caustic soda. NALCO appreciates that the Hon'ble Authority has accepted its contentions of the aforesaid issue as set out in the Disclosure Statement.

6. It is submitted that the petitioner, despite seeking an investigation has sought to pad their cost of production by including in the investigation the cost of production incurred for solid and flakes as well, which are costly to produce, given the fact that further processing is required with respect to them. Further, the commercial perception or market value also differs for solid and flakes on account of the greater Caustic Soda concentration is also reflected in the higher price they command in the market.

7. Further it is submitted that only 30,000 DMT has been imported under the tender which constitutes a minuscule part of the total demand of the country, which as per the petitioner's own admission is around 15,55,200 MT. The imported quantity only totals 1% of the total demand of Caustic Soda in the country and therefore cannot be responsible for the loss alleged by the petitioner.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

8. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France). Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not mean difference in product in terms of various characteristics. Caustic soda is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC Eight Digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 2815.1102 and 2815.1200. The classification, is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

9. It is a well known fact that world over including in India, the Caustic Soda is produced and sold primarily in lye form as (1) Caustic Soda is used in huge quantities, therefore, transportation in lye form even after paying higher transportation cost due to low concentration results in lower effective cost to the purchaser, (2) The conversion of flake requires additional cost. Therefore, the Authority notes that Caustic Soda solid form can be used where lye form is required. The Caustic Soda is produced and sold primarily in lye form as Caustic Soda is used in huge quantities, therefore, transportation in lye form results into lower effective cost even after paying higher transportation for low concentration liquid Caustic Soda. The Authority, therefore, notes that the difference in prices is due to the difference in concentration, higher cost of transportation in lye form vis-a-vis incremental conversion cost required for making solid form.

10. The Authority notes that the goods manufactured by domestic industry are like article to the goods produced, and exported from the subject countries. Both are technically and commercially substitutable and the consumers are using the domestically produced and

imported goods interchangeably. The Authority, therefore, notes that the investigation covers all forms of caustic soda both Lye and flakes, and all different forms of the subject goods are used substitutably depending on the requirement of the user. The Authority in view of submissions made by interested parties and keeping in view the substitutability and interchangeability of the goods exported from subject countries and those produced by the Domestic Industry, considers the subject goods exported and the domestically produced subject goods as like article as per Rule 2(d) of rules Supra. The Authority further for the purposes of dumping margin has made appropriate comparisons on DMT basis only.

C. VIEWS OF GOVERNMENT OF INDONESIA

11. While it is claimed that the domestic industry represents more than 50% of output, the Government of Indonesia notes that the market share of the other Indian manufacturers is far greater than the domestic industry.

12. In fulfilling its obligations under Article 5.4 of the Agreement, the Government of Indonesia wishes to request the Authority to explain the procedures that were undertaken to determine that the application was submitted on behalf of the domestic industry.

13. The determination does not provide any details of the calculation resulting in a dumping margin of 299.87%. As the information used is already in the public domain, there is no justification under Article 6.5.1 of AD Agreement to maintain confidentiality. The Government of Indonesia requests that details of the precise calculation be disclosed.

14. In addition, where an Investigating Authority uses facts available in accordance to article 6.8 of the AD Agreement, the responsibility to exercise due circumspection remains. In this respect, the alleged dumping margin of almost 300% casts a shadow over the quality and accuracy of the evidence used. As such, our Government intends to obtain published information in Indonesia on normal value for the final determination to cover the investigation period (POI).

15. Article 3.7 of the AD Agreement precludes a finding of both threat of and actual material injury. In this respect, we wish to request the Authority to explain the changed in circumstances within the IP that created a situation in which the alleged dumping would cause injury.

16. The performance of the domestic industry in India is quite impressive. In spite of the expansion in domestic capacity utilisation still increased during the POI. During the same period, stocks declined and domestic sales continued to increase.

17. While the alleged dumped imports increased in absolute terms POI, they still represented less than 13% of domestic demand. The Government of Indonesia considers that the volume of imports did not cause the alleged injury to the domestic industry.

18. The different production process to manufacture the subject goods may have a significant impact on cost and selling prices and the alleged injury to the domestic industry may be accounted for by the production process chosen.

19. It is noted that the lesser duty principle has not been applied in this proceeding. The Government of Indonesia would appreciate if an explanation could be provided as to why the LDP has not been calculated.

20. We would hope that the Investigating Authority will observe carefully price movements following the imposition of preliminary measures and if its found that imports are restricted, the impact on the consumer should be re-examined for the final determination.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

21. The petition has been filed by M/s. Alkali Manufacturers Association of India, (AMAI), Delhi on behalf of the domestic industry. The Association represents most of all the domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The petition has been expressly supported by the following domestic producers, i.e. M/s. DCW Ltd., Mumbai, M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Baroda, M/s. Search Chem. Industries Ltd., Mumbai, M/s. Grasim Industries Ltd., Nagda (MP), M/s. SIEL Chemical Complex, Punjab, M/s. Bihar Caustic & Chemicals Ltd., Jharkhand, M/s. Jayshree Chemicals Ltd., Orissa and M/s. Andhra Sugars Ltd., Tanuku. These petitioners companies represents 40.09% of the subject good under production and with support of M/s. Indian Petrochemical Corporation Ltd., Vadodara, M/s. Standards Alkali, Mumbai, and M/s. DCW Shriram Consolidated Ltd., New Delhi, they represent 55.67% of the production of the domestic industry.

22. The Authority notes that the anti-dumping investigations are carried out as per the anti-dumping rule in line with the guidelines of the WTO Agreement. An investigation is initiated on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The application shall be considered to have been made by or on behalf of the domestic industry if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of total production of the like product produced by the domestic industry.

23. Article 5.4 *inter-alia* states that the application shall be deemed to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. In the instant case, Alkali Manufacturer's Association of India is the petitioner and majority Indian producers of Caustic Soda are members of the Association. Further, there is no opposition to the petition expressed by any Indian producer of Caustic Soda. Therefore, the Authority initiated the investigation after determining the level of support as per Rules supra.

24. With regard to market share in demand, it is noted that M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara, M/s. Standard Alkali, Mumbai and M/s. DCM Shriram Consolidated Ltd., New Delhi have supported the petition with complete costing information and the production of these companies with supporter is more than 50% of Indian production.

25. The Authority notes that the normal value has been determined on the basis of domestic price of Caustic Soda in European Union, obtained from a leading International Journal i.e., Chlor Alkali, on the basis of facts available as per Rule 6 (8) of Anti Dumping Rules as none of the exporters from Indonesia have cooperated and furnished the domestic sales price in their home market. The export price was determined on the basis of import statistics from Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata. With regard to calculation of export price, the Authority relied on the information published by the DGCI&S. The DGCI&S information is available in public domain.

26. The Authority notes that the Anti-dumping Agreement does not limit only one form of injury should be present at a time. In fact, in case there is material injury suffered by the domestic industry, it may not be desirable to impose anti dumping duty, unless there is sufficient evidence to show that such injury may continue due to dumped imports which requires redressal for Anti-dumping measures for injury to the domestic industry. The findings on threat of injury recorded by the Designated Authority should be seen as a supplemental finding to the main findings that the domestic industry has suffered material injury.

27. As regards the examination of certain factors of injury under Article 3.4, the Authority examined various injury parameters relating to the domestic industry. With regard to improvement in some parameter, it would be relevant to point out that improvement in few parameter do not imply that the domestic industry has not suffered material injury. Even one single parameter may be sufficient to establish that the domestic industry has suffered material injury. With regard to import volumes, the Authority notes that the imports represented a significant 13% of demand in such a short period. This upsurge in increase cannot be described insignificant.

28. Price undercutting is also significant in this case. The Authority verified the costing data of the petitioners and examined the fair selling price of the industry and arrived at the findings that the landed price of the dumped imports is so low that undercuts the selling price of the domestic industry.

29. With regards to concern of the Govt. of Indonesia about the lesser duty Rule, the Authority notes that the DGAD practices to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or the margin of injury which ever is less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

30. The Authority is in complete agreement with the Govt. of Indonesia that factors such as price depression/suppression are required to be seen by taking actual cost data. The Authority has considered non-injurious price, which is more conservative than the actual cost of production for analyzing the effect of price depression/suppression due to dumped imports.

31. Imports from other countries are either de-minimus or the export price is higher. Therefore, the Authority notes that imports from other countries have not caused injury to the domestic industry.

32. The Authority notes that anti-dumping investigations are product specific and other products have no relevance in these product specific investigations. With regard to injury to participating companies due to other products, it may be noted that all the petitioner companies have furnished information with regard to subject goods only.

33. The Authority also notes that there is no reason for concern that injury to the domestic industry could have been due to other Indian producers. On the contrary, there is positive evidence that the domestic industry has lost market due to dumped imports, prices have declined due to steep decline in the import prices and adverse performance of the domestic industry is due to dumped imports. Membrane process, which is the latest available technology world over is being used by the domestic industry; therefore, difference in the technology hasn't caused any injury to the domestic industry. Since Indian Anti-dumping Rules provide for lesser duty Rule, any such impact due to higher cost of production is automatically restricted

D. VIEWS OF EUROPEAN UNION

34. It cannot reasonably be argued that the information on which the Designated Authority has based its calculation on normal value and export price is of a confidential nature. Regarding European exporters, and according to the document ,provided, normal value data was taken from a "*leading International Journal, i.e., Chlor Alkali*". Export price is said to have been determined "*on the basis of the data collected by them (the petitioners) from DGCI&S*". You are therefore requested to provide, or make available, the detailed information on which these preliminary findings were established.

35. Although provisional duties are based on the difference between the landed price and a target price, this target price varies per country of origin. Why is this target price different? Furthermore, the same paragraph indicates that the amount of anti dumping duty should equal to the margin of dumping. How can this be when it is based on a target, which is based on injury levels found?

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

36. The Authority notes that the normal value has been determined on the basis of domestic price of Caustic Soda in European Union, obtained from a leading International Journal i.e., Chlor Alkali, on the basis of facts available as per Rule 6 (8) of Anti Dumping Rules as none of the exporters from EU (excluding France) have cooperated and furnished the domestic sales price in their home market. The export price was determined on the basis of import statistics from Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata.

37. The Authority also notes that the DGAD practices to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or the margin of injury which ever is less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. It is because of this reason the reference price (target price) varies as per Country of Origin.

E. DOMESTIC INDUSTRY:

38. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

39. The definition of Domestic Industry given above is further clarified by Rule 5 of Rules which reads as follows:-

“----- the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be to the application.”

o to

40. The petition has been filed by M/s. Alkali Manufactures Association of India (AMAI), Delhi on behalf of the domestic industry. The Association represents most of the domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The petition has been expressly supported by the following domestic producers, i.e. M/s. DCW Ltd., Mumbai, M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Baroda, M/s. Search Chem. Industries Ltd., Mumbai, M/s. Grasim Industries Ltd., Nagada (MP), M/s. SIEL Chemical Complex, Punjab, M/s. Bihar Caustic & Chemicals Ltd., Jharkhand, M/s. Jayshree Chemicals Ltd., Orissa and M/s. Andhra Sugars Ltd., Tanaku. These petitioners companies represents 40.09% of the subject good under production and with support of M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara, M/s. Standard Alkali, Mumbai, and M/s. DCM Shriram Consolidated Ltd., New Delhi they represent 55.67%.

41. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, “domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry.” Further Rule 5(3) of the Anti Dumping Rules states that Designated Authority shall not initiate any investigations pursuant to an application made under sub rule (1) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the Domestic Industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the Domestic Industry .

42. The Authority also notes that the domestic producers who have supported the petition constitute more than 50% of the total domestic production and there is no opposition to the petition by any of the domestic producers , therefore, have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5 (3) (a) and (b) of the Anti-Dumping Rules and also represent Domestic Industry in terms of Rule 2(b)

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:

VIEWS EXPRESSED BY M/s. NALCO

43. The petition filed by the domestic industry is misleading and suffers from concealment of material facts. Assuming without admitting that the petition contains true and correct particulars, it is respectfully submitted that the petition lacks sufficient evidence to even justify initiating the investigation. In light of the aforesaid contentions the petition is not maintainable is entirely without merit

44. As regards NALCO's tender giving an option to the supplier to supply from any country in case of imposition of anti dumping duty, it is submitted that the same is incorporated to reduce the tax burden on NALCO, which would have to pay the same. This is put in as a matter of abundant caution, since the product is available in all countries at international price, it can be supplied from any source. NALCO has kept the provision in contract such that it is not saddled with additional liability on account of anti dumping duty. It, if happens provision for cancellation, was kept to safeguard NALCO's interest. If procurement at international price in Global Press Tender and keeping provision in contract such that additional liability does not occur to company is not taken, then NALCO will be required to answer to various agencies of Govt. of India like Audit, Vigilance etc. The petitioner and not NALCO is guilty of abusing the process of this Hon'ble Authority as it has with the present investigation covered all the sources of international caustic soda production.

45. The total imports in the year 2001 in the petition has been mentioned as 35,544 MT and during period of investigation has been mentioned as 1,97,013 MT. It is respectfully submitted that this needs verification since in the earlier anti dumping investigation for same Caustic Soda for import from China and Korea, the Designated Authority in their preliminary findings had noted that the total imports during 2001-2002 was 93,291 MT. It may be pointed out that none of the petitioner could satisfy the tender demand of NALCO forcing it to import Caustic Soda. Therefore the domestic industry either through non participating or in adequate participation has brought about the said import and cannot be said to argue that the same has directly or indirectly injured it.

46. Since Nalco's import is the only basis for this anti dumping investigation and NALCO imports only liquid Caustic Soda. Therefore, the only liquid Caustic Soda should be considered for arriving at whether there is dumping and whether there is any injury to indigenous industries. As earlier informed, the Caustic Soda liquid is completely different from Caustic Soda solid/flexes as solid flexes involve further manufacturing process, thereby the cost of production is different. Their end use is different and market value is also different, since for Caustic Soda solid and flexes, the handling, storage and transportation is completely different from Caustic Soda liquid.

47. The petitioners in their non-confidential version have given the prices offered by overseas supplier, but have deliberately not indicated the prices offered in the tender by domestic parties who are part of the domestic industry in the present investigation. These prices being very near to overseas prices, there cannot be any injury to indigenous industries.

48. In order to determine the true profitability of a Chlor Alkali industry it is important to recognize the revenue realization from both Chlorine and Caustic Soda which are co products arising out of the electronic splitting of common salt. The reaction producing caustic soda produces Caustic Soda and Chlorine in the ratio of 1:0.9. It is a commercial reality that the realization of both Chlorine and Caustic Soda is intrinsically linked to each other and manufacturers determine the price of each in terms of Electro Chemical Unit (ECU) i.e., the total realization from the two and not just individual realizations.

49. Caustic Soda and Chlorine prices almost mirror each other and the prices of the products are inversely proportionate to each other. Therefore when the price of Chlorine is high the price of chlorine is low and vice and versa.

VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:

50. Indian Caustic Soda industry has been largely able to meet entire requirement of Caustic Soda in India. The Indian industry was self-sufficient in its requirement ever since 1975. Caustic Soda has been in the list of imports permitted under OGL particularly for actual users since 1980-81. The imports were, however, limited because of the pricing policy of the Indian industry. The capacities installed by the producers in Chinese Taipei, Indonesia, and EU(excluding France) are far higher than the requirement in their own country. Further, with the imposition of anti-dumping duties on a number of other countries, the producers in the subject countries are finding it lucrative to export to India. The excess capacities in these Countries have put tremendous pressure on the producers to look for markets outside their country. Resultantly, the exporters from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France) have quoted very low prices for exports to India. It would also be relevant to point out that the producers in these countries have at times not directly offered for supplies to India, substantial volumes have been offered by traders in third countries for supply of Caustic Soda originating in these Countries. The offers being by traders, naturally, these traders have taken care of their margins also. The prices quoted by the producers in these Countries are, therefore, still lower. The petitioners believe that the prices offered are far below the associated cost of production. Thus, the exporter from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France) has resorted to dumping of Caustic Soda in the Indian market.

51. Most of the Indian producers are having multi product plant and uses 100% Chlorine for Captive use only and Caustic Soda is a by-product. The actual situation is absolutely different and reverse.

52. The statement made by the NALCO is incorrect as the prices considered by the domestic industry is for lye and does not include flakes, which is evident from the information on record of the Designated Authority.

53. Designated Authority sent questionnaire along with the notice of initiation to known exporters and producers of Caustic Soda in subject countries and Governments of subject countries with a request to advise its producers and exporters of Caustic Soda to respond to the notice of initiation and questionnaire. However, none of the exporters/producers have responded to the Designated Authority. Such being the situation, the Designated Authority is justified in proceeding with the best available information. Normal value was based on prices published in a leading journal, Chlor Alkali. However, in case of Indonesia, it is submitted that the import prices were so low in the investigation period that these prices could not have enabled the producers in subject countries for recovery of their cost of production. Thus, Chlor Alkali prices can not be in the ordinary course of trade. In fact, petitioners strongly suspect that this has been the reason for no response from the exporters. The producers in these countries must be well aware that the prices quoted in Chlor Alkali are very low and would not pass the test of ordinary course of trade.

54. In Caustic Soda the domestic industry is facing injury due to dumping from one after another sources. The present investigation is fourth investigation for the product by the Designated Authority. The domestic industry has no option but to approach the Designated Authority for imposition of anti dumping duty on one after another sources due to shifting of

dumping to newer countries. The tender document conditions of NALCO earlier referred to by the petitioners and reproduced herein below is eye opener in this regard.

"In the event of imposition of Anti Dumping Duty by Government of India after placement of order, the supplier will make all attempts to source supply from other non Anti Dumping origin at the same price and terms and conditions of the order. Time allowed by buyer for arranging material from non Anti Dumping origins from the date of imposition of Anti Dumping Duty by the Government of India will be 30 days. However, if the seller fails to make supply as per above, the buyer reserve right to terminate the order for the balance contract quantity without financial liability on either side. This will not cover for the shipment, which are in transit.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

55. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: -

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

56. Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

57. The Authority provided opportunity to the exporters from subject countries to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority wrote to the Embassies/High Commissions/Representative of subject countries in India also. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of export price and normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act Only M/s. Solvay Belgium filed the response which were incomplete. None of the exporters responded to the preliminary findings and did not offer comment either on dumping or injury.

58. Regarding the argument raised by M/S NALCO about the Chlorine, the Authority notes that for each unit of Caustic Soda, Chlorine is also produced in a particular quantity. However, it is also a fact that Chlorine is hazardous; hence it cannot be freely transported. In India, Caustic Soda plants have been set up as "Caustic Soda Plant" not as a Chlorine plant; therefore, the industry has to be seen for the purpose it has been created. When the producers in India sell Chlorine at available price, credit for the same has been taken in this investigation at relevant places. The Authority notes that the Chlorine is produced in a particular quantity with each unit of Caustic Soda. Hence, it is well known fact that with particular capacity of Caustic Soda plant, how much Chlorine would be produced. It is one of the products produced and sold by the industry and the Authority examined and verified their costing data in these investigations.

EUROPEAN UNION (EXCLUDING FRANCE)

A. NORMAL VALUE

59. The Authority sent questionnaires to all known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A (1)(C). M/s. BASF, Belglum, M/s. BASF, Germany, M/s. Bayer Shell Isoyanates, N.V., Belgium have stated that they have not exported to India during the period of investigation. M/s. Solvay Belgium did not comply to the deficiencies pointed out to them and did not furnish the information in the prescribed exporters questionnaire which is required for the investigation. The exporter didn't offer their comments on dumping and injury.

60. Therefore, in view of the inadequate and incomplete response filed by the exporters from European Union (excluding France) the Authority relied on the information provided by the domestic industry for the purpose of determination of normal value for final findings. Thus the Authority constructed normal value for all producers/exporters on the basis of data provided by the petitioner on the basis of domestic sales price in the domestic market of EU (excluding France) through secondary sources from leading international journal i.e., Chlor Alkali with due adjustments for the subject goods in EU (excluding France).

61. The Authority has referenced the Normal Value for such producers/exporters as ****\$/DMT.

B. EXPORT PRICE

62. The Authority notes that the export price has been determined on the basis of the import statistics of DGCI&S Kolkata. The petitioners claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively which have been taken to arrive at the ex-factory export price.

The ex-factory export price is referenced as ****\$/DMT.

INDONESIA**A. NORMAL VALUE**

63. The Authority notes that none of the exporters from Indonesia have responded by way of questionnaire response and didn't offer their comments on dumping and injury subsequent to the preliminary findings. The Authority in view of non-cooperation has constructed normal value for all producers/exporters of Indonesia on the basis of facts available as per Rule 6(8) of anti dumping rules. Therefore, the Authority constructed the normal value for all producers/exporters on the basis of data provided by the petitioner on the basis of domestic sales price in the domestic market of Indonesia through secondary sources from leading international journal i.e., Chlor Alkali with due adjustments for the subject goods in Indonesia.

The normal value is therefore referenced as ****\$/DMT.

B. EXPORT PRICE

64. The Authority notes that the export price has been determined on the basis of the import statistics of DGCI&S Kolkata. The petitioners claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively which have been taken to arrive at the ex-factory export price.

The ex-factory export price is referenced as ****\$/DMT.

CHINESE TAIPEI**A. NORMAL VALUE**

65. The Authority notes that none of the exporters from Chinese Taipei have responded by way of questionnaire response and didn't offer their comments on dumping and injury subsequent to the preliminary findings. The Authority in view of non-cooperation constructed normal value for all producers/exporters of Chinese Taipei on the basis of facts available as per Rule 6(8) of anti dumping rules. In view of this the Authority has constructed normal value for all producers/exporters on the basis of data provided by the petitioner on the basis of domestic sales price in the domestic market of Chinese Taipei through secondary sources from leading international journal i.e., Chlor Alkali with due adjustments for the subject goods in Chinese Taipei.

The normal value is therefore referenced as ****\$/DMT.

B. EXPORT PRICE

66. The Authority further notes that the transaction wise data received from DGCI&S for the period (January-July) 2002 is not showing any imports from Taiwan whereas M/s. NALCO one of the cooperating importers, has shown the import from Chinese Taipei to the extent of 26189 MT upto April 2002. The Authority in this regard notes, the evidence provided by the petitioner, which indicates that, the offer

was also made by the importer in India during the POI. The petitioner has claimed that M/s. NALCO had floated the tender on 8th July 2002 and the price bid was opened on 13th August 2002 and order was placed to two foreign parties to supply of Caustic Soda originating in Taiwan. The orders for 30000 MT was placed to M/s. Nissho Hawai @ US\$ ****/ PMT and 55000 MT @ US\$ ****/ PMT was placed to M/s. Angulf Polymers and Chemicals The Authority in this regard notes that the date of selling could be date of contract, purchase order, order confirmation, or invoice whichever establishes the material terms of sales. The Authority in view of the evidence and information available on record notes that the exporter has indicated an export price pertaining to the shipment made to India as ****\$/DMT. The petitioners have also claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively.

The ex-factory export price is referenced as ****\$/DMT.

G. DUMPING-Comparison of Normal Value & Export Price

67. The rules relating to comparison provides as follows:

68. "While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

69. The Authority has followed the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of the Anti Dumping Rules. Based on the Normal values and Export prices as indicated above the Authority assessed the Dumping Margins in case of all exporters/Producers from the subject countries as given in the table below:-

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Sl. No.	Country/ Exporter/Producer	Normal Value (\$/MT)	Ex-Factory Export price (\$/MT)	Dumping Margin as % of EP
1	EU(excluding France) All exporters/producers	****	****	124.97%
2	Indonesia All exporters/producers	****	****	99.76%
3	Chinese Taipei All exporters/producers	****	****	89.95%

The above Dumping Margins are above the de-minimus limits.

H. INJURY AND CAUSAL LINK:

70. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

- i. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- ii. While examination the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 19 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY:

71. Annexure II (iii) under Rule 11 supra further provides that “in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti Dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual country is less than three percent ,the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles”.

VIEWS OF M/S NALCO:

72. NALCO has submitted that the alleged sole grievance of the petitioner is the loss of the NALCO tender floated on July 8, 2002 for 115,000 MT. Therefore the peculiarity of the NALCO demand alone should be considered by the Hon'ble Authority in arriving at the issues of like product, dumping, injury and causal link. It is submitted that NALCO, like any other manufacturer of alumina, only use lye Caustic Soda and not solid and flakes. Thus the

Hon'ble Authority should only consider the cost of production of lye Caustic Soda alone should be considered in arriving at the issues of dumping, injury and causal link.

73. NALCO has further submitted that only 70000 MT has been imported under the tender, which constitutes a minuscule part of the total demand of the country, which as per the petitioners own admission is around 15,55, 200 MT. The imported quantity totals 4.5% of the total demand of the Caustic Soda in the country.

74. The determination of injury should be done considering realization both from Caustic and Chlorine together not from Caustic alone. From the price summaries report of Chlor Alkali, it may be seen that North-America when the Caustic contract price in July, 2002 was in the range of US\$ 80 – 100 DST FOB, the Chlorine contract price was in the range of US\$ 235 per ST. This being the price difference in international market if cost of production and realization is considered separately as being adopted by Designated Authority it gives distorted view. Therefore, the total realization from Caustic and Chlorine should be considered to determine if there is any dumping by any manufacturers. As earlier mentioned both product being co-generated manufacture is interested in total realization from Caustic Chlorine together rather than on any one product.

75. NALCO appreciates that the Hon'ble Authority has accepted its contentions on the fact that any determination of the non-injurious price would need to consider the valuation of Chlorine a valuable co product in the generated in the production of Caustic Soda. NALCO hereby reiterates its contentions set out in its submissions dated March 10, 2003 wherein the accounting process for the costs of caustic soda and chlorine has been set out in greater detail and the contents of the same are not repeated herein for the sake of brevity.

76. It is submitted that the high cost of production in India for Caustic Soda is attributable to the high cost of power, as essential input, in the country. The high cost of power coupled with the inefficient storage process followed by the domestic manufactures in India with respect to chlorine should be taken into account by the Hon'ble Authority in any determination of a non-injurious price.

77. It is submitted that the Chlor Alkali report has been used as the basis for arriving at the normal value. However, the rates set out in the petition do not indicate the month for which they have been taken. This has greatly inhibited the ability of NALCO to respond to the case allegedly set up against it. Further, it is respectfully submitted that as the NALCO tender is the sole triggering event for the present investigation, the most appropriate period for the determination of a normal value would be the rates prevailing in the market when the tender was finalized. This would also be advisable on account of the price volatility in the Caustic Soda and Chlorine markets. Further, the high cost of production on Caustic Soda is on account of the high cost of electricity, a fundamental input required for producing Caustic Soda.

VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:

78. Petitioner has argued that nowhere in the petition it is mentioned that the investigation is NALCO centric and duty should be imposed on imports made by NALCO only. So far as

loss of tender floated by NALCO is concerned, it is a fact that the domestic industry has lost a significant part of the tender to dumped imports. In addition, there are other importers/consumers who consumed significant quantities of imported Caustic Soda from subject countries. Therefore it is misleading to say that the whole investigation is NALCO centric. It is nowhere mentioned in the petition filed by the domestic industry that the investigation is NALCO centric investigation and duty should be imposed on imports made by NALCO only. This argument of NALCO is its own creation.

79. So far as loss of tender floated by NALCO is concerned, this is a fact that the domestic industry has lost significant part of the tender to dumped imports. In addition to NALCO, there are other importers/consumers, who consumed significant quantities of imported Caustic Soda from the subject countries. Therefore, it is misleading to say that the whole investigation is NALCO centric.

80. It would be worthy to mention here that the domestic industry itself has preferred anti dumping in variable form so that no anti dumping duty is charged in case the export price is just and fair.

81. NALCO is not the sole producer of Aluminum in India. Internationally also, argument of NALCO lacks appreciation of even the basic definition of dumping. Dumping would occur only when the export price to India is lower than domestic price. Such being the case, it is a fallacy on the part of NALCO to believe that the world consumers of Aluminum would be getting the material at equally dumped prices.

82. The fact is that NALCO has tried all possible means to resort to imports of Caustic Soda, with complete disregard to its impact on the Indian producers. In fact, these very exporters of Caustic Soda to NALCO have backtracked on their commitment to NALCO and it is the Indian Producers who had come to the rescue of the company.

83. Cris Infac has worked out variable margin by reducing salt and power cost from gross realization from Caustic Soda and Chlorine. Thus, NALCO has assumed that the whole cost incurred by the Caustic Soda producers are only on account of salt and power and there are no other costs incurred in production and sale of Caustic Soda. It is unbelievable that NALCO has concluded that there are no other costs involved in production and sale of Caustic Soda (except for salt and power). NALCO has conveniently chosen to ignore the costs on account of other raw materials, salary and wages, repairs and maintenance, consumables, other manufacturing overheads, depreciation, finance, administration, selling & general, etc. incurred by any producer of Caustic Soda world over. The fact is that costs on these accounts represent a significant chunk of cost of production.

84. Cris Infac report at best can be considered as referring to the contribution earned by the producers to meet their other costs. However, even this report suggests that variable margins for the industry declined significantly over the years. Cris Infac report, thus, at best establishes that the margins for the domestic industry have declined and the domestic industry has suffered material injury. It should also be noted that Cris Infac determines these variable margins after considering realizations from Caustic Soda and Chlorine. Thus, even on combined realization basis, the margins of the domestic industry have declined.

85. It is undisputed fact that part of tender was allotted to the domestic producers also. However, the domestic industry has capacity and capability to meet full and complete

requirement of NALCO as well as Indian demand. Argument of NALCO that the domestic industry is making profits is without knowledge and appreciation of facts. Petitioners have represented their actual data to the Designated Authority and the same is relied upon.

86. The domestic industry has suffered material injury from the dumped imports. It is evident that:

- (a) Imports from subject countries have increased in absolute term. Imports, which were negligible earlier, reached to a high level in very short period, which clearly shows that the exporters are trying to take benefit of imposition of anti dumping duty against other countries by resorting to dumping. In fact, the volume of imports in the current investigation period crossed all historical levels since 1980.
- (b) Imports from subject countries have increased in relation to production in India.
- (c) Market share of imports from subject countries in relation to total imports in India has increased.
- (d) Market share of imports from subject countries in demand of the product in India has increased.
- (e) Production of the domestic industry has increased, resulting in increase in capacity utilization. The increase in production is a result of imposition of anti dumping duty on a number of countries one after another.
- (f) Sales volumes of the domestic industry have increased marginally in the period of investigation.
- (g) The domestic industry has lost significant sales volume due to dumped imports due to lost orders of NALCO tenders.
- (h) Though the sales of the domestic industry increased, the domestic industry has not been able to increase its profitability.
- (i) Export price from subject countries have declined significantly resulting in decline in landed value. This has caused severe price undercutting and price suppression/depression in the Indian market.
- (j) The market for Caustic Soda is highly price sensitive, where a difference of small amount would result in substantial loss of sales. In fact, the price increases/reductions affected by the industry sometimes are very low. Therefore, the consumers find any difference between landed price of imports and selling prices of the industry quite lucrative.
- (k) The landed price of imports is below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry. Thus, the imports are having significant suppressing/depressing effect on the prices in the domestic market.
- (l) Caustic Soda industry has provided very large-scale employment in the country. Any sickness in the industry would have crippling effect not only on the direct employment but also very large-scale indirect employment in the country. While the companies have policy to retain its employees even in tough conditions, due to continued losses, the employees are demoralized and not sure of their future.
- (m) The domestic industry is making financial losses from each unit of sale of Caustic Soda in the Indian market. The financial losses are in spite of imposition of anti dumping duty on a number of countries, due to shifting of imports to newer dumped sources.
- (n) Inventories of the domestic industry, which were increasing earlier, declined in the period of investigation.
- (o) Productivity of the domestic industry increased due to increase in production.
- (p) Return on capital employed of the domestic industry remains negative.

(q) Wages of the employees with the domestic industry have increased. Even in situation of losses, the domestic industry has no option but to increase wages due to prevailing laws. Furthermore, any decline in wages would have crippling effect on the production.

(r) As submitted earlier, the domestic industry is making losses. Continuous losses to the domestic industry have resulted in negative effect on cash flow of the companies.

(s) Apart from the injury being suffered by the domestic industry, there is a threat of further injury being caused to them on account of dumped imports.

87. During the period of investigation imports from subject countries have increased at a significant rate, which is causing further threat of material injury to the domestic industry;

88. Manufacturers and exporters from the subject countries are holding substantial surplus capacities and stocks.

89. Serious concern of domestic industry is on the price at which the product is being imported. The price at which the material is being exported is a dumped price. Further, the material is entering the market at prices much below the selling prices of the domestic industry.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

90. The Authority has taken into account all indices regarding injury while doing the final determination. This would involve all relevant facts viz., volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market and its subsequent effect on domestic producers, production, capacity utilisation, profitability, net sales realisation etc. While determining the non-injurious price for the like article for the domestic industry, the Authority considered the optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and would also take into account the actual price of the raw materials during the period of investigation which go into the production of the product under consideration.

91. It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than deminimus. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority, therefore, proposes to assess injury to the domestic industry from the subject countries cumulatively.

92. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

93. Following parameters establish that material injury has been caused to the domestic industry from dumped imports from the subject countries;

	Particulars	Unit	1999-00	2000-01	2001-02	Jan-Sept' 02	Annualized
Sales	Indexed	100.00	99.37	100.58	100.71	100.71	
Cost of Production	Indexed	100.00	93.05	98.47	86.83	86.83	
Selling Price	Indexed	100.00	116.61	130.40	99.26	99.26	
Profit/Loss	Indexed	-100	-47.29	-36.47	-62.69	-62.69	
Capacity		809800	809800	822300	822300	822300	
Trend (Indexed)		100	100	101.54	101.54	101.54	
Capacity Utilization		89.96%	91.57%	90.01%	70.29%	93.72%	
Production	MT	728526	741555	740192	578000	770667	
Trend	Indexed	100.00	101.79	101.60	105.78	105.78	
Market Share (Imports)							
European Union	MT	298	19964	173	12746	19119	
Taiwan	MT	0	19033	327	85000	127500	
Indonesia	MT	14860	0	4972	26031	39047	
Subject Countries	MT	15158	38997	5472	123777	185666	
Trend	Indexed	100.00	257.27	36.10	816.58	1224.87	
Other Countries	MT	81921	40434	38781	74588	99450	
Total Imports	MT	97079	79431	44253	198365	285116	
Market Share in Imports							
European Union	%	0.31	25.13	0.39	6.43	6.71	
Taiwan	%	0.00	23.96	0.74	42.85	44.72	
Indonesia	%	15.31	0.00	11.24	13.12	13.69	
Subject countries	%	15.61	49.10	12.37	62.40	65.12	
Other countries	%	84.39	50.90	87.63	37.60	34.88	
In Demand							
Merchant Demand	MT	1391534	1409949	1406129	1161611	1548815	
Trend	Indexed	100.00	101.32	101.05	111.30	111.30	
Captive Consumption	MT	202260	233726	209728	172479	229972	
Demand	MT	1593794	1643675	1615857	1334090	1778787	
Trend	Indexed	100.00	103.13	101.38	111.61	111.61	
Market Share in Demand							
Domestic industry Incl. Captive	%	45.27	45.62	45.30	42.33	42.33	
Trend	Indexed	100.00	100.76	100.07	93.50	93.50	
Domestic Industry Excl. Captive	%	32.58	31.40	32.32	29.40	29.40	
Trend	Indexed	100.00	96.36	99.21	90.24	90.24	
Other producers	%	48.64	49.55	51.96	42.80	41.64	
Trend	Indexed	100.00	101.08	106.83	88.00	85.62	
Subject Countries	%	0.95	2.87	0.34	9.28	10.44	
Trend	Indexed	100.00	249.46	35.61	975.54	1097.48	
Other Countries	%	5.14	2.46	2.40	5.59	5.59	
Trend	Indexed	100.00	47.86	46.69	108.77	108.77	

Particulars						
Productivity (Per Employees)						
Employees	Indexed	100.00	98.46	97.22	127.36	95.52
Productivity per employee	Indexed	100.00	163.38	104.51	110.74	110.74
Return on Investment						
Return on capital employed	%	-12.58	-5.88	-4.60	-7.81	-7.81
Inventories	MT	6511	8233	15080	21652	21652
Trend		100	126.44	231.60	332.53	332.53
Employees	Nos	4421	4353	4298	4223	4223
Trend	Indexed	100	98.46	97.22	127.36	95.52
Wages	lacs	5649.17	5684.45	6603.55	4827.75	6437.00
Trend	Indexed	100	100.62	116.89	113.95	113.95

Volume and Market share of dumped imports

94. Imports of Caustic soda from subject countries have increased significantly in (i) absolute terms; (ii) in relation to production; and (iii) in relation to the consumption in India. While the imports are primarily from many countries, but share of imports from EU (excluding France), Indonesia, and Taiwan have increased significantly during the period of investigation in relation to the demand in India. The share of imports from subject countries has increased from 12.37% in 2001-2002 to 62.40% during the POI (annualized). Imports are coming from many other sources but those imports are either di-minimus or attracting anti-dumping duty. It is evident from the above that the imports have increased in relation to production of the domestic industry.

95. The production and capacity utilization of the domestic industry has increased during the period of investigation. This increase in the production and capacity utilization is due to the fact that demand has also increased. The rate of growth of imports of subject goods is much more than the rate of growth of domestic production and demand of Caustic Soda.

96. The petitioner companies determine their prices based on prevailing market conditions. The market prices were driven by the lower prices of the dumped imports as the share of dumped imports has increased from 12.37% in 2001-02 to 62.40% during the POI(annualised).

97. Though domestic sales volumes of the domestic industry have marginally increased, the selling price of the subject goods has significantly declined. Further, domestic industry could not reduce its selling price to match dumped imports. The landed price of imports is so low compared to the cost of production and selling price of the domestic industry that the domestic industry is not in a position to reduce its price to match the price of imported subject goods. The Authority, therefore, notes that in this prevailing situation the domestic industry lost both the profit and the market to compete with the dumped imports.

Market share in demand

98. The share of domestic industry (Incl. Captive) in demand has decreased from 45.30 % in 2001-2002 to 42.33% in the POI (annualised) where as the share of domestic industry (Excl. Captive) in demand has decreased from 32.32 % in 2001-2002 to 29.40% in the same period. The other producers have also lost their share significantly in demand roughly around 10% which have been taken by the dumped imports from subject countries. The share of imports from other countries has also increased by 3% without affecting /injuring the domestic industry, since these imports are coming at undumped prices. The demand in general has increased from 101.38 in 2001-2002 to 111.61 in POI; however, this increase in demand has mostly been occupied by the dumped imports from China. Therefore, the Authority notes that the dumped imports have displaced the market share of domestic industry because of dumped imports of caustic soda from subject countries.

Inventory and evidence of loss of contract

99. The Authority notes that the inventory stocks have increased from 15080 MT in 2001-2002 to 121652 MT during the POI (annualised). The Authority holds that the increasing trend in stocks along with the displacement in the market in the POI (annualised) is due to the dumped imports from the subject countries.

100. It has been claimed that because of the decline in export price, the domestic industry is forced to match the selling price with the export price and keep the selling price at a level to compete; in this process the domestic industry is not able to recover the marginal cost. It is further claimed that the domestic industry is unable to sell Caustic Soda at such a low price resulting loss of contract. The Authority holds that due to the dumped imports, the domestic industry is forced to sell the product at a loss.

Price undercutting and Price underselling

101. There are a number of parameters evidencing injury, should the imports be allowed at the present dumped prices. The rate of increase of imports during the period of investigation from subject countries and the corresponding fall in profits of the domestic industry are the parameters clearly showing the injury being suffered by the domestic industry. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury. It has been observed that the dumping has had a significant impact on the net sales realisation of the domestic industry for the subject goods. To preserve its market share the petitioner had to compete with low priced and dumped imports of the subject goods from the subject countries. The landed price of the dumped imports indicates the evidence of severe price undercutting.

102. The Authority notes that the price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the fair selling price of the product under consideration and compared the same to the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level of incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. The imports were having significant suppressing/depressing effect on the price of the domestic market, as the domestic industry is not able to raise its selling price in view of the dumped imports. Thus the examination of the available evidence shows that the domestic industry as a whole suffered injury on its sales of subject goods during POI. The Authority has determined the extent of price undercutting and price underselling during the POI and holds that domestic industry has suffered significant price undercutting and price underselling during the POI due to dumped imports from the subject countries.

Employment

103. The employment level of domestic industry has consistently been declining from the last three years and the index has come down to 95.52 during the POI (annualised) from 100 in 1999-2000. The Authority notes that this change in employment is due to the significant loss to the domestic industry and a cost cutting measure to maximise the efficiency and productivity. The Authority, however, notes that this decline in level of employment cannot be ascertained that led to injury to the domestic industry.

104. The productivity of the domestic industry has not improved even after a reduction in the number of employees. However, it is also observed that the production per employee has increased, whereas production per day declined significantly.

Profitability

105. The unit cost of production has declined from 100 in 1999-2000 to 86.83 in the annualised POI whereas unit selling price has also marginally declined respectively from 100 in 1999-2000 to 99.26 in the annualised POI. The unit selling price has not declined in proportion to the cost of production which led to the betterment in financial loss which still did not help much in improving the financial health of the domestic industry. The domestic industry is incurring the loss due to the fact that the domestic industry is forced to reduce the selling price below its cost of production, to hold on market, due to dumped imports from subject countries. The industry has suffered the material injury on account of depressed selling price resulting in non-recovery of cost of production thereby suffering financial losses.

106. While cost of sales, production value and sales value have also increased; the increase in the cost of sales is more than increase in the sales value. This has directly resulted in decline in the profits of the domestic industry. Production and sales volumes of the domestic industry has increased, however, it is found that in spite of increase in production and sales volumes, the profitability of the domestic industry has significantly deteriorated. Thus, increase in production and sales volumes have not helped the domestic industry in improving its profits.

Growth and return in investment

107. The demand for the product has increased however, the growth of the domestic industry has declined significantly. The imports are retarding the growth of the domestic industry in spite of significant increase in demand in the country. It is claimed that due to dumped imports from subject countries the domestic industry is doubtful to achieve the target or even to raise capital from the market unless remedial measures is taken to prevent dumped imports from subject countries. The Authority notes that it would be difficult for the domestic industry to plan fresh investments.

108. Cash Profit of the domestic industry declined during the period of investigation, thus adversely affecting the cash flow situation of the domestic industry.

109. Further, the increase in the wages has resulted in further increase in the cost of sales, whereas the domestic industry could not maintain its profits. The Authority notes that the domestic industry has no option but to increase wages as per prevailing regulations in the country. However, the wage increases are further adversely affecting the profitability, as the domestic industry is not able to proportionately increase the prices.

Cumulative Assessment

110. It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than deminimus. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The circumstances of the present case fully meet conditions of cumulative assessment given in the Annexure II of the Rules, as (1) margin of dumping from each of subject countries is more than the de minimus limits; (2) share of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and (3) the imported material is directly competing with the domestic material. The Authority, therefore, notes that all relevant factors cumulatively and collectively establish that the domestic industry has suffered the material injury during the period of investigation due to dumped imports.

111. As regards the threat of injury, the Authority notes that the Anti-Dumping Rules states as follows:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the DA shall consider, inter-alia, such factors and;

- a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b) Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,
- d) Inventories of the article being investigated.

112. Regarding the threat of material injury the Authority has noted that there is a significant increase of dumped imports during the POI i.e. 123777 MT compared to 5472 MT during 2001-2002. The Authority further notes that these imports from subject countries significantly undercut the prices of the domestic product forcing the domestic industry to sell at unremunerative prices. Further the material is coming at a price much below the selling price of domestic industry and if the domestic industry starts selling at this price, the same would result in huge financial loss to the domestic industry. The order placed by M/s. NALCO in favour of supplies from the subject countries would also result in a loss of significant volume to the domestic industry.

113. There is also likelihood of substantially increased imports from these sources in view of huge production in these countries. It is further noted that there is surplus

capacity available in the subject countries, which could be a matter of concern to the financial performance of the domestic Industry if the same is utilized for exports to India at dumped prices. Further, existence of significant price undercutting would result in significant increased importation, if the imports continue in the same pace at dumped prices.

114. Performance of the domestic industry in the present investigation period and injury to the domestic industry from the dumped imports originating in subject countries is required to be seen in the context of anti dumping duties earlier imposed. The domestic industry has earlier suffered material injury from Saudi Arabia, USA, Japan, Iran, France, Qatar, Korea RP, and China for which the anti dumping duties are in force.

115. With the imposition of anti dumping duty on some sources, vast Indian market is obviously quite lucrative to those who are holding surplus capacities or are not having sufficient domestic demand. Under the present circumstances, the threat of injury is not a remote possibility or conjecture, but real and imminent in Indian market.

116. The Authority notes that the rate of increase of imports during the period of investigation from subject countries and the corresponding fall in the sales realization and profits of the domestic industry are the parameters clearly showing the injury being suffered by the domestic industry. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury and is suffering further threat of injury during the period of investigation. Therefore the Authority notes that the domestic industry is facing a threat of material injury due to dumped imports from subject countries.

117. The Authority further notes that the non-injurious price has been evaluated for the various domestic producers by appropriately considering the sales realisation from the related products. Also in order to eliminate inefficiencies, the Authority has normated and benchmarked the best practices on utilisation of raw materials, utilities etc.

118. As regards the injury, which could happen on account of higher cost of production in India, the Authority notes that under the Indian Anti Dumping Rules it is the lesser duty rule which is applied. Further in any event the anti dumping duties cannot exceed the dumping margin.

119. The Authority is led to conclusion that all relevant factors, cumulatively and collectively establish that the domestic industry has suffered the material injury during the period of investigation. The imports are further causing threat of material injury.

I. CAUSAL LINK:

120. In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts: -

121. Substantial imports of subject goods from subject countries at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to un-remunerative level, which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.

122. The imports from subject countries suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

123. The imports from subject countries have forced the Domestic Industry to reduce the selling price, which has adversely affected its profitability.

124. The Authority, therefore, notes from the above that the imports from the subject countries have been arrived at a price below the selling price of the domestic industry. Further, the imports into India have been at a price lower than the non-injurious price for the Domestic Industry. As a consequence, thereof, the Domestic Industry has not been able to earn a reasonable return on their investment. These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports and further causing threat of material injury.

125. The share of volume of dumped imports in total consumption has increased from 0.34% in 2000-01 to 9.28% during POI. The market share of the domestic industry fell from 45.30% in 2000-01 to 42.33% during POI. The dumped imports were coming into India at price that significantly undercut the prices of the like domestic product. The prices of dumped import have caused both price depression and price suppression on the prices of the like domestic products. Thus both volume and price effect is established.

126. There is no contraction in demand (demand has rather increased). Further, there is no other factor such as trade restrictive practice or development in technology, which could have material injury to the domestic industry. Increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India have directly resulted increase in the sales, which further resulting in decline in the share of the domestic industry in the demand of the product in the country. Further, the low prices of imports have prevented the domestic industry from optimizing their profitability.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

127. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

128. The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

129. The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

130. The Authority has not merely relied upon the submissions of the petitioners regarding fair selling price, rather the Authority deputed a team for on-the-spot investigation and verification of costing and manufacturing process of various forms of caustic soda, and worked out in detail the fair selling price of caustic soda in India for the Domestic Industry separately.

131. Consumers have raised their arguments that the imposition of anti dumping measures would result in less competition and higher prices for consumers of caustic soda and may harm the user industry. The Authority notes that price advantages based on unfair practices are unjustifiable and may in the longer term be harmful even to the interest of consumer.

132. The Authority has not merely relied upon the submissions of the petitioners regarding fair selling price of Caustic Soda, rather the Authority deputed a team for on-the-spot investigation and verification of uses of Caustic Soda in manufacturing of Alumina by M/S NALCO in presence of one of petitioners M/S DCW Limited who has been supplying caustic soda lye in Railway Tank Wagons through sea. During the course of verification, the Authority noted that M/S. DCW Limited did not supply them caustic soda lye from December, 2001 to February, 2003 as price offered by them were uneconomical, whereas, from March, 2003 orders for 38,500MT have been accepted on a reasonable fair price.

J. CONCLUSIONS:

133. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Subject goods have been exported to India from subject countries below its normal value;
- (ii) The Indian industry has suffered material injury and facing threat of further injury;
- (iii) The injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries.

134. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty on all imports of Caustic soda from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the Petitioner Companies determined for the period of investigation.

135. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties as set out below be imposed by the Central Government on all imports of Caustic soda falling under customs heading 2815.11 & 2815.12 originating in or exported from subject countries. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column no.9 of the following table and the landed value of imports per MT on all imports of subject goods falling under chapter 28 of the Customs Tariff, originating or exported from the subject territory/countries mentioned below:-

Sl. No	Sub-headings	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda	Chinese Taipei	Any Country	Any Producer	Any Exporter	US \$271.46	Metric Tonne	
2	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda	Any country except Indonesia and Eu(excluding France)	Chinese Taipei	Any Producer	Any Exporter	US \$271.46	Metric Tonne	USD
3	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda	Indonesia	Any Country	Any Producer	Any Exporter	US \$271.46	Metric Tonne	USD
4	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda	Any country except Chinese Taipei and Eu(excluding France)	Indonesia	Any Producer	Any Exporter	US \$271.46	Metric Tonne	USD
5	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda	EU(excluding France)	Any Country	Any Producer	Any Exporter	US \$258.46	Metric Tonne	USD
6	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda	Any country except Chinese Taipei and Indonesia	EU (Excluding France)	Any Producer	Any Exporter	US \$258.46	Metric Tonne	USD

136. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
137. Subject to the above, the Authority confirms the Preliminary Findings dated 8th January, 2003.
138. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority